The motion was adopted

Clauses 2 to 8, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI SHAHNAWAZ KHAN I move

' That the Bill be passed "

MR DEPUTY-SPEAKER The question is

"That the Bill be passed '

The motion was adopted

DISCUSSION RE FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY

MR DEPUTY-SPEAKER Now we take up discussion under Rule 193 on the flood and drought situation in the country

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी-गढवाल). उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सर्व-विदित है, आज देश भर मे बाढ का जो प्रकोप हुआ है, उस के कारण लाखो घर तबाह हो चुके है । हम वर्षो से देखते आ रहे है कि हर साल जब जब बाढ आती है, उस के बाद हमारी सरकार के घडियाल के आसू तो बह ये है, किन्तु बाढ की स्थायी रोक-थाम के लिए, उस के निराकरण के लिए उसने आज तक कोई ठोस कदम नही उठाया है । अब तक केवल टीके लगाने की ही प्रक्रिया अपनाई गई है और जो बाढ से क्षतिग्रस्त परिवार है, उन को थोडी बहुत सहायता पहुचाने का प्रयास तो किया गया है, किन्तु उससे जो क्षति हमारे देश को पहुच रही है, हर साल जो करोडो रुपये की सम्पत्ति नष्ट होती जा रही है, उसको बचाने के लिए सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम अभी तक नही बनाया गया है ।

मैं उदाहरण के रूप मे निवेदन करना चाहता हू कि चतुर्थ पचवर्षीय योजना के लिए सरकार ने 153 करोड रुपये का प्रावधान किया है, जब कि आवश्यकता कम से कम 100 करोड रुपये की है ।

यही नही मे एक बात और निवेदन करना चाहता हू कि सरकार ने चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो अथवा प्रान्तीय सरकार, बाढ के मूल स्थान पर जहा से बाढ का उद्गम होता है उन स्थानो पर बाढ की रोकथाम के लिए कोई योजना न अब तक तीन योजनाओ मे रखी है और न चतुर्थ पच वर्षीय योजना मे उस के लिए कोई प्रावधान किया गया है । मै उदाहरण के लिए निवेदन करना चाहता हू कि फ्लड कट्रोल को अब तक जिन चार भागो मे विभाजित किया गया है उस मे कान्स्ट्रक्शन आफ एम्बैंकमेट्स ड्रेनेज स्कीम्स टाउन प्रोटेक्शन स्कीम्स और रेजिग दि विलेज एबव दि फ्लड लेवेल यही चार बाते रखी है । किन्तु कैचमेट एरियाज जो कि नदियो के है उनमे बाढ की रोकथाम के लिये कोई योजना सरकार ने अभी तक तैयार नही की है । 1951 मे जबकि फ्लड कट्रोल का काम शुरू किया गया तब से अब तक केवल 250 करोड रुपये इस मे व्यय हुए है जबकि हम देखते है कि हर साल अरबो रुपये की सम्पत्ति इसके कारण नष्ट होती रही है ।

भारत सरकार की इरीगेशन एड पावर मिनिस्ट्री की एक विशेषज्ञ समिति ने जो इस पर जाच की थी वह इस परिणाम पर पहुचा थी कि हमको कैचमेट एरियाज मे फ्लड कट्रोल के लिये सबसे अधिक ध्यान देने का आवश्यकता है और मै आपको सूचना के लिए एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट-टेक्निकल रिपोर्ट आन ऐन आन-दि स्पाट स्टडी आफ दि अलकनंदा ट्रैजेडी, 1970 से एक छोटा सा अश का उद्धरण करना चाहता हू । उसमे कहा गया है—

"The damage on the Rishikesh-Joshimath Road were followed by a localised cloud burst in the area around the source of water feeding the Patal Ganga, Rishi Ganga and Dhauli Ganga "

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

फोर्थ वर्ल्ड फारेस्ट्री कांग्रेस जो कि 1954 में हुई थी उसके उद्घाटन भाषण में श्री के० एम० मुंशी ने उस समय कहा था—

> "People naturally turn to the engineering structures to hold the rivers within their banks....these measures, important and of immediate use as they are, seek to cure the symptoms, not the disease.. the flood control has to begin at the beginning, by enforcing proper management of the catchments of rivers and reconditioning of the mountain sides."

और एक सेमिनार हुआ था—सेमिनार आन इंजिनियरिंग ज्यालाजी प्राबलम्स इन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन नार्दन इंडिया, उसमें जो पेपर अलकनंदा की बाढ़ के सम्बन्ध में पढ़ा गया था उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया था कि कैचमेंट एरियाज में बाढ़ की रोकथाम करने के लिए आवश्यकता है। पिछले वर्ष जब अलकनंदा ट्रैजेडी हुई थी उस समय डा० के० एल० राय ने कहा था कि वह एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेंगे जो कि बाढ़ के कारणों की जांच करेगी और रोकथाम के उपाय सुझाएगी। मेरी जानकारी में कमेटी की कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई है और जहां तक मेरी जानकारी है उस कमेटी के विशेषज्ञ तो क्या शायद गांव का एक पटवारी भी उस स्थान तक नहीं गया जिसका कि नाम गोहना लेक कहा जाता है। यह जो फ्लड वहां आया उसकी कोई जांच पड़ताल किसी ने नहीं की है।

यह बात बहुत कही जाती है कि बांध बनाने चाहिए और उससे बाढ़ की रोकथाम हो सकती है। किन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। एक इंटर प्राविंशियल कमेटी अप्वाइंट हुई थी गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से 1939 में, उसने सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया था कि बांध बनाना एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर तो हो सकता है लेकिन उससे कोई स्थायी हल बाढ़ का नहीं निकल सकता है। इसी संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांध बन जाने के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही और उनकी अकर्मण्यता का प्रमाण हमको देखने को मिलता है। बिहार में पिपरासी में जो क्षति हुई है और उत्तर प्रदेश में छितौनी के पास रेलवे लाइन जो क्षतिग्रस्त हुई उसमें अधिकारियों की यह लापरवाही देखने को मिलती है। पिछले वर्ष अलकनंदा की बाढ़ के फलस्वरूप जो क्षति पहुंची और ऐंटीबायटिक्स में जो करोड़ों रुपये की दवाओं को क्षति पहुंची है वह भी बहुत कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पहुंची है। उसकी जिम्मेदारी भी अधिकारियों की ही है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1948 में एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी बाढ़ की जांच पड़ताल करने के लिए और उस कमेटी ने 1954 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। मैं आपका ध्यान फिर से कैचमेंट एरियाज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा था—

> "The biggest contributory factors for the increase in the frequency of and intensity of these floods are improper agricultural practices and abuse and destruction of forests and grassland.

उसी रिपोर्ट में आगे पृष्ठ 86 पर लिखा हुआ है—

> "Only construction of bundhs will not be effective for flood control, especially for long-range planning. Bunds are costly to build and maintain. As a matter of fact flood water should be checked in the upper catchments before it is allowed to assume an uncontrollable volume.

और फिर पृष्ठ 143 पर लिखा हुआ है—

> "There should be a concerted and systematic reafforestation of the catchment areas of all rivers and streams, particularly in the hilly areas. The expenditure on any such scheme will be more than compensated by the accruing permanent benefits to the country."

इस रिपोर्ट के अलावा भारत सरकार की भी जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट मे काफी जोर कैचमेंट एरियाज के लिये दिया था। लेकिन हमे खेद के साथ कहना पडता है कि इन कमेटियो की जितनी भी रिपोर्टें होती है वह या तो रद्दी की टोकरियों मे रख दी जाती है या अलमारियो को सजाने के काम आती है। उनका इम्प्लीमेंटेशन नही किया जाता है। आपने सुना होगा वैली आफ फ्लावर्स का नाम बहुत मशहूर है जिस पर अंग्रेजो ने भी ग्रंथ लिखे है और आज भी पर्यटक वहा जाते है। लेकिन आज वहा आप जाय कोई भी फूल देखने को नही मिलता है। इसका कारण यह है कि वहा पर नोमेडिक ट्राइब्स के लोग, घुमतु लोग जो होते है वह अपने पशुओ को लेकर, भैंसो और भेडो को लेकर जाते है और न केवल उन्होने वहा के फूलो को नष्ट कर दिया है बल्कि पहाड के सभी स्थानो को चरने चुगाने से इस तरह तहस नहस कर दिया है कि सारी वेजीटेबल ही वहा की नष्ट हो गई है। इसके कारण भी फ्लड की प्राबलम पैदा हो गई है। इसलिये आवश्यकता इस बात की थी जैसी कि यू० पी० गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी ने भी सिफारिश की थी और जैसी कि भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने भी सिफारिश की है कि इन एरियाज मे एफारेस्टेशन होना चाहिए और चरान चुगान के लिए ऐसे कडे नियम बनाने चाहिए ताकि पहाडो पर बाढ न आ सके और जब पहाडो पर बाढ नही आएगी तो मैदानो मे भी बाढ नही आएगी। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हू, स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू 1938 मे हवाई जहाज से गढ़वाल गए थे तो तब उन्होने एक लेख मे लिखा—

> "From the air we saw Garhwal spread out below us with bare mountains, and its narrow valleys, with rivers winding through them....partly this problem of water has been aggravated by the lack of forests and general barrenness of the hill-sides. It is then the fault of the men, of the ignorant cultivator, or the incompetent or careless Government."

इसमे शक नही कि उस समय अंग्रेजो का शासन था 1938 मे और उन्होंने अंग्रेजो की आलोचना की थी लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि आज यदि वह होते तो हमारी राष्ट्रीय सरकार के बारे मे क्या धारणा रखते जब कि तब से लेकर आज तक और भी क्षति वनो को पहुची है बजाय इसके कि हम और अधिक वन वहा पैदा करते।

मिनिस्ट्री आफ इरिगेशन एण्ड पावर ने एक हाई लेवल कमेटी आन फ्लड्स बनाई थी, उसने बाढ की विभीषिका की जो जाच-पडताल की थी, वह भी इसी नतीजे पर पहुचा थी कि जो सबसे अधिक क्षति है, वह गगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा होती है और उस कमेटी के अनुसार 1950 से 1956 के बीच मे देश भर मे बाढ से 323 करोड रुपये का नुकसान हुआ, जिसमे से गगा और उसकी सहायक नदियो के द्वारा 203 करोड रुपये की क्षति हुई। इसलिये मै निवेदन करना चाहता हू कि इन स्थानो पर बाढ की रोक-थाम के लिए हमारी सरकार को और अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मै कुछ सुझाव देना चाहता हू—यदि हमको बाढ की रोक थाम करनी है, तो सबसे पहले हमारी सरकार को पहाड के क्षेत्र मे, कैचमेंट एरियाज मे री-एफोरेस्टेशन करना चाहिये और ऐसे कडे नियम बना देने चाहिये, जिससे पहाडो मे भैंस, बकरी और भेड़ों के चुगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

दूसरी बात—यह जो फ्लड प्रोटेक्शन का काम है, इसको फूड प्रोडक्शन के काम की तरह से लिया जाना चाहिए। कुछ समय पूर्व हमारी प्रधान मत्री श्रीमती इदिरा गाधी जी ने सुझाव दिया था कि फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम की तरह से इसको नेशनल डेवेलपमेंट प्रोग्राम का

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली]

अनिवार्य अग बना कर चतुर्थ पच वर्षीय योजना से विशेष स्थान देना चाहिए।

तीसरी बात—मैदानी इलाको मे जितनी हमारी नदिया है, उन सबको शीघ्र-से शीघ्र एक दूसरे से जोड देना चाहिये। नेशनल वाटर ग्रिड की नितान्त आवश्यकता है। यदि यह हो गया तो हमे एम्बैकमेट पर जो खर्च करना पडता है, वह न करना पडेगा और एक तरह से बाढ के समय जो क्षति पहुचती है, उस क्षति से देश को बचा सकेगे।

हमारी नेशनल फारेस्ट पालिसी जो पहले की बनी हुई है, उस मे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस लिये है कि हमारे पहाड के लोगो के पास आजीविका के दूसरे साधन नही रह गये है। लोगो के अन्दर जमीन की भूख है इसलिये वे जहा-तहा जमीनो को काट कर, जगलो को साफ कर के खेती के द्वारा साधन जुटाने की फिक्र मे रहते है। आवश्यकता इस बात को है कि पहाड के क्षेत्र मे, चाहे वह गढवाल का क्षेत्र हो, चाहे नेफा का क्षेत्र हो, सब स्थानो पर अधिक से अधिक वन उपजाये जाय, अथवा फलोत्पादन किया जाय। क्योकि पहाडो से हम देख रहे है—पिछले 20-25 वर्षो मे बेतहाशा जगल कटे है। और खेतो पर अधिक से अधिक लोग निर्भर रहने लगे है। इसलिए यह काम नितान्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय बाढ के कारण गढवाल के क्षेत्र मे—अलमोडा, नैनीताल, पिथौरागढ मे जो भयकर क्षति पहुची है, घर तबाह हो गये है, एक तरह से भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत से परिवारो को आज जगल की जडी-बूटियो और घास पर निर्भर रहना पड रहा है। मेरे पास ऐसे अनेको पत्र भी आये है, जिस मे लोगों ने लिखा है कि हमे बिच्छू-घास (स्कार्पियन प्लाट) खाकर जीवित रहना पड रहा है क्योकि उन के खेत समाप्त हो गये है। पिछली फसल तो चौपट हो ही गई है, भविष्य की भी कोई आशा उनके पास नही रह गई है। इसलिये इन बातो को ध्यान मे रखते हुए मै अनुरोध करना चाहता हू कि आप फौरन प्राइम मिनिस्टर्ज रिलीफ फण्ड से वहा पर सहायता भेजने का प्रयास करें। दूसरे—जिन लोगो की खेती चौपट हो गई है, उनके लिये तत्काल आजीविका का कोई साधन सुलभ कराये।

मै मत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हू कि आपको वर्क-फार-फूड-स्कीम से भी जो सहायता उस क्षेत्र का दी जा सकती है, उसको शीघ्र सुलभ कराने का प्रयास करे।

मैदानो मे बाढ आती है तो एक बार तो पानी भर जाता है, लेकिन जब बाढ निकल जाती है तो उन स्थानो पर उससे खुराक मिलता है, खेती मिलती है, लेकिन पहाडो मे जब बाढ आती है तो गाव के गाव बरबाद हो जाते है, हमेशा के लिये समाप्त हो जाते है और फिर उनका दोबारा बनाना सम्भव नही रह जाता है। इसलिये यदि आप सोर्स के स्थान पर मूल स्थान पर बाढ के रोक-थाम की कोशिश करेगे तो मै विश्वास के साथ कह सकता हू कि हमारी यह समस्या हल हो सकती है, बाढ का प्रकोप कम हो जायगा।

इन शब्दो के साथ मै निवेदन करना चाहता हू कि आप बाढ की जो विभीषिका है उसको रोकने के लिये तत्काल कोई कदम उठाये और जो पीडित व्यक्ति है, उनको अविलम्ब सहायता देने का प्रयास करे। पहाडो मे कैचमेट एरियाज मे रि-एफोरेस्टेशन का काम करें और नेशनल वाटर ग्रिड की योजना को चतुर्थ पच वर्षीय योजना मे सर्वोच्च प्राथमिकता दें -

14.46 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

*SHRI KRISHNA HALDER (Ausgram): Hon. Mr. Chairman, today in this House I

*The Original speech was delivered in Bengali.

would like to speak in Bengali. You know, Sir, that our country is full of rivers. It was also agriculturally very much prosperous. During the regime of the British Government our rivers very much neglected. The policy of the British Government was merely to exploit us. They did not frame any plan for our rivers. Consequently, the river water, which is required for the development of our agriculture, became a great source of flood devestation in our country. Every year lakhs of people became victims of floods. They also become homeless. Standing crops in lakhs of acres lands are also destroyed. After the floods famine is the usual vistor. People also suffer on account of epidemics.

There has been a loss of Rs. 204 crores due to the floods in 1968. In the same year there has been a destruction of food crops in 205 lakhs acres lands and at that time lakhs of people also became homeless. In 1969 the extent of loss due to the floods was Rs. 333 crores. In that very year, in the entire country, there has been a destruction of food crops in 236 lakhs acres land.

Mr. Chairman, you know, Sir, that is 1970, due to the floods, there has been a loss of food crops in the entire country worth Rs. 100. crores. Crops in 151 lakhs acres lands were destroyed in that very year. We, therefore, find that in every year, due to the floods, the extent of loss on average of foodgrains comes to Rs. 211 crores in valuation.

After 25 years of our Independence we thought that a scheme would be undertaken by the Government on a National scale regarding our rivers in order that our country may be saved from flood havocs for good. Sir, the hon. Minister of Irrigation said that this year monsoon came earlier than the past years. The rainfall also was heavier this year than the past years. Consequently, the flood havoc this year in greater than the past years. But even after 25 years of our independence we do not find a national flood control scheme. If there had been a national flood control scheme in our country, then, lakhs of people would not have been homeless every year.

People living in U. P. Bihar, West Bengal and Kerala usually become victims of floods. Recently the people of Rajasthan have also become victims of floods. But who are those people ? They are all poor people. Generally it has been found that in every year the poor people are the worst sufferers on account of floods. These poor people mostly come from the scheduled castes and scheduled tribes communities, agricultural labourers, share croppers and factory workers.

It is our assessment that the Government is required to spend rupees one thousand to one thousand and five hundred crores for the flood control measures in the country. But we have found that the Central Govenment has so far speent Rs. 250 crores for the flood control measures. That is why we find the recurrence of flood havocs in various parts of the country.

Mr. Chairman, you know, Sir, that after the establishment of democratic Government in Communist China the feroscious Yangsi river was controlled by that Government and it was utilised for the benefit of the people. The Chinese Government adopted a plan to control this river. The Government also inspired the people to contribute their labour in order to implement the said plan. In this manner the people of China were saved from the frequent flood havocs of the Yangsi river. But in our country we do not find such type of efforts by our Government in regard to flood control measures. If our Government had conducted any scientific inquiry into the nature of rivers like Ganga, Narmada and Teesta and other rivers, it would have been possible for us to check the fury of floods, caused by these rivers every year in our country. After knowing the nature and direction of the rivers, it becomes possible for us to find out thh remedial measures in regard to checking the floods.

In every year floods occur in our country. It occurs because we have not yet undertaken any scientific river research. Besides, we have not yet framed a national plan in regard to flood control measures.

My previous speaker said that our rivers in many places are drying. In order to check this we must adopt a plan of afforestation at the source of the rivers. The present situation has developed for want of any afforestation plan from the Government.

DVC plan is there for us. But inspite of that, in lower Damodar valley, we suffer a loss of Rs. 20 to 25 crores every year owing to

[Shri Krishna Halder]

the floods. Hundreds of villages and lakhs of acres lands are inundated by flood waters every year there. There 8 dams were proposed to be constructed in order to arrest flood waters. But only 4 dams have been constructed there. It would have been possible to prevent flood havocs in lower Damodar valley if the Man Singh Committee report had been implemented. Besides, if bunds had been constructed over Damodar river in low lying areas and by constructing Sluice gates if the river water had been diverted through various channels for irrigation purposes, the places like Hooghly, Howrah and Arambagh sub-division would have been saved from flood havocs every year. We know that floods occur during rainy season for the surplus rain water are not diverted through various channels systematically. We know that floods occur in lower Damodar valley as the surplus rain water is not released according to some plan. We also know that Rs. 14 crores is required to implement the lower Damodar valley scheme and the drainage scheme. But the Government has sanctioned only Rs. 25 lakhs. According to us, this amount of money is not at all adequate for the purpose. We therefore demand that Rs. 4 crores should be sanctioned for implementing the said schemes so that they may be completed within three years. Completion of these schemes will save people of lower Damodar valley from sufferings every year.

Ajoy river and Kunur river cause floods every year. The Government must, therefore adopt flood control plans for Ajoy and Kunur rivers. Floods occur three times in a year in my constituency. People of atleast 7 villages there will have to be shifted to some other place for rehabilitation. I again demand that necessary steps may be taken by the Government to formulate flood control plans for Ajoy and Kuuur rivers.

Many tributaries from Uttar Pradesh have joined the Ganga in Bihar. But the Bhagirathi river has dried. Now, Bhagirathi has become a tidal creek except rainy season.

Therefore, the Farrakha barrage project must be completed as soon as possible. From that project 40,000 cusecs water will have to be released all the time in order to feed Bhagirathi and for silt clearance.

MR. CHAIRMAN: There are so many names on the list of speakers. If one member takes more time, I shall be unable to accommodate all the members.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): We can sit till midnight.

MR. CHAIRMAN: No, no.

SHRI KRISHNA HALDER: I again appeal to the Government to undertake flood control measures and also to implement afforestation plan. Already 18 people have been killed by the recent floods in Malda. Lakhs of acres cultivable lands have been destroyed. The Government must therefore take necessary steps to check floods. every year, you give large amount of money as gratuitous relief to the flood victims. I therefore say that instead of spending money like this on gratuitous relief the Government must formulate a national flood control plan. I would request the Irrigation Minister, Planning Commission and the Finance Ministry to sit together for the formulation of the said plan. My further request is that the said plan should be implemented on a war footing. If the Government does not do anything to check the floods, people are likely to be victims of famine and epidemics. A day will come when the flood-affected people will stand united against the present Government and the incurrent of their united struggle will flood that Government away.

So, after serving this warning upon this Government, I again demand that the flood control measures in our country should be implement in right earnest.

MR. CHAIRMAN: Dr. Austin.

SHRI SHANKARRAO SAVANT (Kolaba): Our names are already there. Will we be called?

MR. CHAIRMAN: I will call one after the other.

SHRI N. N. PANDEY: All States have been affected either by flood or by drought. So all States should be represented in this debate which is a vital matter to all. UP and Bihar are most affected.

Several Hon. Members *rose*—

MR. CHAIRMAN : We have just begun. There is enough time. Let members not be impatient. They will have opportunity to press their demands.

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam) : The mid-monsoon fury has wrought severe havoc throughout our country in a heavy toll of life and property. June and July this year had been months of agonising calamity for our country. Bihar, Eastern UP, Assam, Rajasthan, Punjab, Kerala and many other States have been heavily affected by this natural calamity.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar) : Orissa also.

DR. HENRY AUSTIN : I said 'other States' also.

15.00 hrs.

AN HON. MEMBER : Orissa.

DR. HENRY AUSTIN : I am sorry. Orissa and other States as well. I was only highlighting some of the most-affected States.

Public opinion demands the application of engineering skills and other techniques. Public opinion was also focussed on spending more money to prevent or contain this annaul challenge and the calamities which cost the country about a crore of rupees every year. The hon. Minister for Irrigation and Power, in estimating the losses, has said that in the course of the next 10 years, an annual expenditure of Rs. 40 crores would be needed to meet this calamity. It is very gratifying to note that in the fourth five year Plan, Rs. 138 crores have been provided to meet this challenge. But we have yet to find additional reasurces according to the estimate of the hon. Minister and we have to try other sources also.

I think numerous geophysical and ecological factors contribute to the floods during the monsoon season. The rainfall pattern, the nature and intensity of the winds, thermal variations, the state of the soil in specific areas, forest cover and even ai pollution, which has a bearing on precipitation—these are some of the scientific aspects of the problem. This may not be entirely in the hands of technocrats, but I think some studies have to be made into this aspect. Some revers can be tamed by dams, detours and canals. An intensified afforestation programme can be launched. More refined methods of forecasting should be arranged, Flood warning and evacuation problems should also be attended to. But to put the blame entirely on the Government will be to refuse to accept the harsh realities of a tropical country like ours. So, in this background we have to approach this problem. After having made this preliminary observation from the general angle, I would like to focus the attention of the House for a minute or two on the devastation that has taken place in my constituency in Kerala.

In Kerala, anti-sea erosion problem is the major problem. Every year, vast areas of rich land greatly useful to the country are being washed away. When I was a child, within a few miles of my own house, there were huge deposits of rare earths like monazite, zircon, ilmenite and rutile. These are of vital and basic importance to our country for the development of nuclear energy for constructive purposes. In the last 30 years, most of the lands have been washed away and this is almost an aggression by the sea. Even as the frontiers of our country are being protected in various ways, this gradual encroachment by sea into vast areas of our natural frontiers has to be prevented and the areas have to be guarded, I think the hon. Minister is a competent person ; he is a technocrat himself, and so, adequate measures will have to be taken forthwith.

Let me just take the example of a tiny country like Holland. What scientific measures they have taken to protect their country from sea-erosion ? Why not this great country adopt similar measures ? After all, according to the hon. Minister it requires only Rs. 40 crores to protect the coast of Kerala. In my own constituency, from Chellanam to Kannamaly over 40 families have been uprooted and nearly 2,000 acres of land have been submerged. Almost the whole of coastal Kerala has been affected by this June and July havoc. 25,000 people have been uprooted. This is an annual occurrence.

I do not want to dilate on this. The Chairman has already said that he is pressed for time. I would only like to make this suggestion. Anti sea erosion measures will have to

[Dr. Henry Austin]

be immediately attended to. The hon. Minister is seized of the situation, and I am sure he will take necessary steps to make this a Central subject. The Centre gives occasionally some money to the States and the State Governments do some work. I suggest that the Centre should consider this a national problem, constitute an Anti-Sea Erosion Board directly under the control of the Minister and see that the anti-sea erosion work is undertaken as early as possible.

As long as you are not able to make permanent arrangements, those affected by this erosion every year should be given relief in immediately, instead of hutting them to such difficulties. The Centre should create a reserve fund for helping those uprooted:

I only wanted to focus the attention of the hon. Members and the hon. Minister on this situation which is recurring every year with the present-day advance in science and technology, it should not be difficult for us to meet this challenge:

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, हमारे देश के साथ···

SHRI ANANTRAO PATIL (Khed): Those who have given notice of the motion, whose names appear in the order paper, should be called first. We have been waiting for this debate for the last 15 days.

सभापति महोदय : देखिये एक बात है। पार्टी वाइज नाम हमारे पास आते है उसी हिसाब से मेम्बरों को समय देना पड़ता है। मैं महसूस करता हूं कि बाढ़ से करीब-करीब सभी प्रान्त अफेक्टेड हैं और जितने सदस्य हैं सभी अपनी बात को रखना चाहते है। बाढ़ की वजह से बड़ी ग्रेव सिचुएशन पैदा हो गयी है जैसे माननीय हैनरी आस्टिन ने कम समय में ही अपने पौइंटस को मिनिस्टर के सामने रख दिया वैसे ही अन्य माननीय सदस्य भी करें तो अधिक लोगों को ऐकोमोडेट किया जा सकता है, जो मै करना चाहता हूं। अतः आप लोग समय कम लें और केवल पौइंट्स को रख दें, यही हमारी रिक्वेस्ट है।

कुछ लोगों ने जो अपने नाम दिये हैं वह यही है। पार्टी की तरफ से दूसरे नाम आये हैं। तो हम कभी इस में से फालो करते हैं और कभी दूसरी लिस्ट में से फालो करते है यही तरीका हो सकता है।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Kangra): First preference should be given to the sponsors of the motion.

SHRI SHANKARRAO SAVANT: I have enquired of the party office, and they have told me that the names given to the Chair are in addition to the names of the sponsors.

सभापति महोदय : हम कोशिश कर रहे है कि हर प्रांत का एक-एक, दो-दो आदमी बहस में हिस्सा ले ले। यह न हो कि एक प्रांत के ज्यादा आदमी हिस्सा ले लें और दूसरा प्रांत बाई डिफाल्ट चला जाय। इसलिये इस में समय मत लगाइये और बहस चलने दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : हमारे देश के साथ प्रकृति व्यंग और अट्टहास कर रही है। प्रकृति की अजीब माया है। कही धूप और कहीं छाया वाली कहावत सम्पूर्ण देश में चरितार्थ हो रही है। अतिवृष्टि के कारण हमारे देश की तमाम नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण चौदह राज्य इससे ग्रसित हैं, बुरी तरह से ग्रसित हैं। एक तरफ तो बाढ़ की वजह से विनाश लीला है और दूसरी तरफ हमारे देश के कई राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और उसकी मार से वहां की जनता कराह रही है। बिहार, असम दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काशमीर, केरल मध्य प्रदेश, मणिपुर, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल ये चौदह राज्य बाढ़ से ग्रसित है। पानी न पड़ने की वजह से, सिचाई की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, असम और तमिलनाडु के इलाके प्रभावित हुए हैं, वे सुखाड़ से ग्रसित हैं। बाढ़ पीड़ित राज्यों में से सब से ज्यादा खराब स्थिति बिहार की

है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और बद्रीनाथ का पहाड़ी इलाका है, वे भी बाढ़ से पीड़ित हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा मालदा जिलों की हालत भी बहुत खराब है। हिमाचल प्रदेश की हालत भी खराब है। केरल के नौ जिलों मे बाढ़ आ गई है। असम की भी हालत खराब है। धन जन की अपार बरबादी हुई है। अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। मंत्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट मे कहा है जिस को उन्होंने सदन पटल पर कुछ दिन पहले रखा था कि 215 करोड़ रुपये की बरबादी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अकेले बिहार मे लगभग तीन अरब रुपये की बरबादी हुई है। इस तरह से अरबो रुपये की बरबादी हुई है। सड़के नष्ट हो गई है, बाध टूट गए है, मकान ढह गए हैं। इस सब के कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। मंत्री महोदय कहते है कि केवल 107 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

बाढ़ की विभीषिका से उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, गोरखपुर आजमगढ़, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, हमीरपुर जालौन आदि जिले प्रभावित हुए है। केरल में मालघाट, कालीकट, अलप्पी, त्रिवेन्द्रम, कन्नानोर, त्रिचूर, क्विलोन, अरनाकुलम, ये नौ जिले प्रभावित हुए हैं। इन में से पांच जिलों की स्थिति बहुत ही खराब है मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां सी इरोशन, समुद्र के कटाव का सवाल है केरल के लिए वह बहुत बड़ा सवाल है। इसी वास्ते केरल की सरकार ने केन्द्र से कहा कि उसे इस समुद्र के कटाव से बचाया जाए और इसके लिए उसे 150 करोड़ रुपये दिये जायें। बाढ़ रोकने की जो योजना है उससे अलग से यह राशि उसने मांगी है। खुद केरल की सरकार ने दो करोड़ रुपया सहायता कार्य के लिए मांगा है और वह उसको दिया जाना चाहिये।

बिहार की बाढ़ सचमुच अद्वितीय बाढ़ हैं। बिहार के लोगों का कहना है कि बिहार के इतिहास में ऐसी बड़ी बाढ़, ऐसी सत्यानाशी बाढ़ कभी नहीं आई थी। सतरह जिलों में से चौदह जिले इससे पीड़ित है। ये जिले हैं पटना शाहाबाद, गया, पलामू, हजारी बाग, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, संथाल परगना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चम्पारन, सारन। ये जिले बुरी तरह से बाढ़ से ग्रसित हैं। बिहार के अन्दर जितनी भी नदिया है, जैसे गगा, पुनपुन, सोन, कोसी, गंडक, पचाने, महाने, सकरी, बागमती, आदि सब मे बाढ़ आई हुई है। आज बिहार की सब से नाजुक स्थिति है। बहुत से शहरों में पानी घुस आया है। पटना बिहार की राजधानी है। उस पर खतरा मौजूद है। पटना दानापुर, खगौल मोकामा, आरा, मुगेर, जमालपुर, सोनपुर, कटिहार, बेगूसराय, खगरिया, छपरा, पूर्णिया आदि शहरों में बाढ़ का पानी घुस आया है। मोकामा, एवं कई जगह करोड़ों रुपये का जो सरकारी गल्ला रखा हुआ है, उस पर खतरा उत्पन्न हो गया है। आप तो जानते ही है कि गुप्ता बांध टूट जाने की वजह से डेढ़ सौ करोड़ रुपये का जो इंडस्ट्रियल कम्प्लैक्स बरौनी मे है, उस पर खतरा आ गया था। बाध क्यों टूटे, इसकी जाच होनी चाहिये। इस तरह से बिहार म 460 प्रखडों मे से 217 प्रखड बाढ़ से प्रभावित है। बिहार सरकार ने नैचुरल कलेमिटी एक्ट के मुताबिक वहा अकाल की स्थिति घोषित की है और लोगो की मदद की जा रही है। 44,160.6 स्कवेयर मील में फसल नष्ट हो गई है। 13,634 गावों में बाढ़ आई है। 91 प्रतिशत मकई की फसल नष्ट हो गई हैं। 65 प्रतिशत दूसरी फसलें नष्ट हो गई हैं। पाच लाख लोगों को गावों से हटा कर ऊंचे स्थानों में ले जा कर बसाया गया है। बिहार में तीन अरब रुपये की क्षति हुई है। सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। मै केवल बिहार की बात आपको बता रहा हूं।

जहा से मैं आता हूं, पटना, उस जिले में लगभग पचास आदमी मर चुके है। स्वयं मेरे क्षेत्र में आसोपुर ग्राम के चार व्यक्ति डूब चुके हैं। इस तरह से पूरे सूबे की स्थिति खराब है और पटना, मुगेर, पूर्णिया आदि कुछ जिलों की

[श्री रामावतार शास्त्री]

हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। पटना के 28 के 28 ब्लाक पानी के अन्दर हैं। एक भी प्रखंड बाकी नहीं है जहां पानी न हो। बिहार सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्र से 68.22 लाख रुपये की मांग की है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह राशि कम है यह कम से कम एक सौ करोड रुपये यानी एक अरब होनी चाहिये। तभी बांधों की मरम्मत हो सकती है। लाखों घर जो पानी की वजह से गिर गए हैं, उनके मालिकों की हम मदद कर सकते हैं। तभी उनके खाने पीने का बन्दोबस्त हम कर सकते हैं। एक अरब जब तक आप नहीं देंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। खुद मंत्री महोदय पटना गए थे। उन्होंने कहा था कि पटना, शाहाबाद आदि इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए पटना से कोइलवर तक बांध बनाना होगा। इसके बारे में एक स्कीम भी है लेकिन अभी तक उसको कार्यान्वित नहीं किया गया है। उसको कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

पशुओं के लिए चारे की बहुत कमी अनुभव की जा रही है। पशुओं को खाने के लिए चारा नही मिल रहा है। खुशी की बात है कि रेल मंत्री ने कहा कि चारा ढोने के लिये हम डिब्बे देंगे। मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि आप चारा फौरन भिजवायें। आदमियों को तो आप कुछ न कुछ दे रहे हैं। पर पशुओं के लिए चारे की वहां कुछ व्यवस्था नहीं है। इसे आप फौरन करें। दवाओं की भी व्यवस्था आप करें। वे वहां नहीं हैं या उनकी वहां कमी हैं। कर्जे भी आप उनके लिए दें। उसके वास्ते पैसा दें। पीने का पानी अस्वस्थकर हो गया है। उसका भी उपाय करें। किसानों को बीज देने की व्यवस्था करें। श्रमिकों के लिए कठिन श्रम योजनायें चालू करें। सड़कों और मकानों की मरम्मत की व्यवस्था करें। बांध बनाने की तरफ ध्यान दें। जब तक आप यह सब कुछ नहीं करेंगे तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। बाढ़ और सुखाड़ से लड़ने के लिए आपको लम्बे समयकी अवधि के लिए योजना बनानी होगी और इस तरफ फौरन आपका ध्यान जाना चाहिये।

बाढ़ बराबर बहुत से प्रदेशों में आती है और हमारे प्रदेश में तो वह हर साल आती है। लेकिन ऐसी बाढ़ आज तक नहीं आई थी। सरकार पिछले चौबीस बरसों से प्रयत्न कर रही है, लेकिन न वह बाढ़ की रोक सकी है और न सुखाड़ को। इन दोनो को रोकने के लिए लांग-टर्म और शार्ट-टर्म योजनायें बनानी होंगी। सरकार लांग-टर्म योजना को खुद चालू करे और उस को अपनी देख-रेख में पूरा करवाये। इस काम को स्टेट गवर्नमेंट्स पर छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। बाढ़ से बचने के लिए पश्चिमी बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों की जो योजनायें है, सरकार उन को चालू करे और पूरा करे।

जिन राज्यों मे बाढ़ आई है, उन्होंने केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मांगी है, मंत्री-महोदय को वह सहायता मुक्त-हस्त से देनी चाहिए। उसमें किफायत या कंजूसी न करना चाहिये। ऐसा करने पर ही हम लाखों लोगों की जानें बचा सकेंगे और बाढ़ की वजह से जो असीम बर्बादी हुई है, उस की कुछ क्षतिपूर्ति कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों ने जो मांगे रखी हैं, उन पर विचार कर के उन को पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए।

SHRI SHANKARRAO SAVANT: Mr. Chairman, Sir, inscrutable indeed are the vagaries of the monsoon. The entire well being of our country; is bound up with the timely visitation of monsoon but its visits being completely uncontrollable and unpredictable we become helpless before it year after year. This year the monsoon has inundated parts of U. P., Bihar, Orissa and West Bengal and has washed away not only cattle and crop but has submerged villages after villages. Its over-generosity in the North is counter-balanced by its frugality in Maharashtra and Mysore.

In Maharashtra we have a drought of unprecedented magnitude. Coming as it does on the tails of the last year's drought it has inflicted an absolutely unbearable damage. As many as 21 out of 26 districts are affected by

it some six or seven of which are intensely and intensively affected and all told over 23,000 villages are threatened with famine. There is no water to drink both for cattle and for human beings and no grass for the cattle. The Maharashtra Government has started some famine relief works but the response is so tremendous that there is no work that can be given to them. Persons who were till June this year classed as well-to-do are coming forward to work on famine relief works for their daily ration. It is a pitiable sight to find men and women clamouring for work. The despondency so generated is creating new problems of law and order.

Last year only 9 districts as against 21 of this year were affected and the loss was assessed at Rs. 200 crores. The loss in crops this year is simply incalculable. In several districts there are no sowing operations.

Both floods and droughts are bad but a comparison between them is a bit instructive. Flood causes immediate and instant loss of life and property but it leaves a trail of alluvial deposit which enriches the soil and ensures better crops next time while drought is something like a slow lingering death. Cattle die a slow death for want of water and fodder. Men migrate and even die for want of food and water and the entire economy of the region is not only disrupted but even devastated. Despondency and disaffection change the very psychology of the masses which hits at the roots of organised social life.

Under the circumstances I should like to suggest the following short-term and long-term measures to meet the flood and the drought situation in the country. Central teams should be despatched to the affected areas to assess the damage. Adequate financial support should be given to the States concerned. Maharashtra alone needs about Rs. 15 crores by way of subsidy and loan.

At least half of the irrigation projects in Maharashtra, which have been held up on the ground that there is a tribunal appointed to adjudicate the dispute, should be cleared. As many as 11 major and 23 medium schemes of irrigation, totalling 34 in all, of Maharashtra have been held up while only one major and two medium schemes of Andhra have been held up by the Central Government on the ground of appointment of a tribunal. This injustice should be immediately removed and Maharashtra should be allowed to take up at least half of the schemes that is, 16 or 17 schemes, which have been held up.

There should be a big canal joining the Ganges to the Godavari. It will act as a flood prevention measure in the north by taking away the surplus water of the Ganges and its tributaries and will irrigate lakhs of acres of land in UP, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra and will also provide cheap water transport. I am very particular about this because it will not only join north and south but it will be a good flood prevention measure so far as all the northern States are concerned. I am told that this was at one time under the consideration of the Government but it has been side tracked now. I hope that the present Irrigation Minister will pay special attention to it. It will solve not only the problems of the north but of the south also.

So, both these short-term and long-term solutions should be resorted to by the Central Government and the drought and flood situation should be faced adequately.

SHRI RANABAHADUR SINGH (Sidhi): Sir, I would like to draw the attention of this august House towards the flood situation that has come to a part of Madhya Pradesh. These two seem to be unrelated because so far Madhya Pradesh has been a State which, because of its topography, has always remained unaffected. But this year during the last month's rain the rivers Banas and Sone, both of them, have caused the washing away of nearly 50 villages.

Ordinarily, in low-lying areas, where people are accustomed to the ravages of floods, villagers are aware of what precautions to take when the waters come up. Unfortunately, this area in Madhya Pradesh, which has been affected, namely that of the districts of Sidhi and Shabdol, had never had the experience of flood. Accordingly, when this time the water rose about 20 feet above the flood level during the previous monsoon, the villagers were absolutely unprepared for it and there has been a large scale hardship that has come about, specially because the river at that height does not carry silt and most of the deposits that have been deposited on the lands

[Shri Ranabahadur Singh]

of the villagers, whose area has been inundated has been in the nature of sand. So, not only have the villagers lost their homes but also their agricultural land which has been affected by sand deposits and has been made absolutely unfit for cultivation. At the same time, because this flood was absolutely unexpected, the villagers had no time to take away their grain and seeds. So, the present condition is that the land has been affected by sand and even if the sand has not come up to the villagers' fields they have lost their seeds.

So, we are faced with a situation where about 50 villages in Sidhi and Shahdol districts of Madhya Pradesh have lost their land, their seeds and their homes. I would suggest that some effort should be made to make seed available to the villagers who have lost them. Since in that region the forest produce has been nationalised most of the *adibasis* who live there have not been able to get any bamboos or timber to construct temporary shelter for themselves. I would appeal to the Government here to take up the matter with the State Government to see that the laws of nationalised forests are relaxed in favour of the *adibasis* so that they can prepare some temporary shelter till the rain is over and it will be possible for them to move back to their homes. I would also appeal to this august House and the hon. Minister that he should intercede with the State Government and see that some relief measures are immediately made available to this region, specially in the nature of *taccavi* loans for those who want to construct new houses, and also for those who want to clear their land of the sand that has been deposited there.

Finally, I would say that in order to obviate any further recurrence of such debacle the Minister should give urgent thought to the construction of the Banasagar project which, had it been there this situation would not have arisen. This project would be a great boon to our region. I would plead with the Minister not to delay it any longer and see to it that it is taken up as early as possible.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगज) : सभापति जी, ऐसे तो बाढ़ हर साल किसी न किसी देश के हिस्से में आती है, लेकिन मैं अपने मित्र श्री रामावतार शास्त्री की तरह अंतर्राष्ट्रीय तो हूं नहीं, मेरा क्षेत्र सीमित है, इसलिए मैं अपने यहां की बात आप से कहूंगा। यह हर साल एक रिचुअल सा हो गया है कि फ्लड डिबेट हो, कुछ सुझाव दिए जायं लेकिन उन पर कहां तक काम होता है या नहीं होता है यह कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि हर साल डिबेट होती है, हर साल बाढ़ आती है और हर साल नुकसान होता रहता है।

इस साल का फ्लड अभूतपूर्व था कम से कम हमारे इलाके मे और उस की सब से बड़ी खूबी वह थी कि बहुत दिनो तक टिका रह गया। पहले फ्लड आता था, दो चार, पांच दिन रहता था, चला जाता था। इस बार पन्द्रह दिन से भी अधिक हो गए बाढ का पानी जहा आया वही टिका हुआ है, निकलता नही है। मै ने देखा, 5-6 तारीख को मै गया था, लोग छप्परों पर और पेड़ो पर चढ़े हुए है। वहा सड़को के ऊपर 5 फुट 7 फुट तक पानी है। लोगों के घरों के छप्परों के ऊपर से पानी बह रहा है। एक गाव मे एक घर के सब लोग ऊपर छप्पर पर चले गये थे। एक लड़का एक बक्से पर सो रहा था। किसी को मालूम नही था, वह वही रह गया। दीवार गिरी, वह उस मे दब गया। बाद में लोगों ने तलाश की और जब मलबा हटाया गया तो उस की लाश निकली। मैं ने देखा कि एक औरत आठ दस घंटे तक पानी में खड़ी रह गई। वह पानी से बाहर निकली ही नही। बाद में मालूम हुआ कि उस के पास केवल एक साड़ी थी जिसे रात में वह निचोड़ कर डाल देती थी और सुबह पहनती थी। बीच में कोई फटा चिथड़ा कपड़ा पहन लेती थी। बाढ़ में उस की साड़ी बह गई। लोगों को मालूम नहीं था कि उसकी क्या हालत है। चूंकि वह पानी में से निकली नहीं। तब लोगों ने बताया कि उसकी कैसी हालत है इसलिए यह नहीं निकल रही है। मैं ने तुरन्त एक साड़ी और एक कुर्ता खरीद कर उसे दिया तब वह बाहर आ सकी। मक्के के ऊपर 6 फुट 7 फुट पानी है। ईख के ऊपर 6 फुट 7 फुट

पानी है। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या हालत लोगों की होगी। मैं यह नहीं कहता कि यह फसल बह गई, वह फसल बह गई। फसल बहने का क्या सवाल ? लोगों की स्थिति इतनी भयानक है, इतनी दर्दनाक है कि क्या कहूं। नाव नहीं कि उन को रेस्क्यू किया जा सके। जो पावर बोट्स है वह इतनी थोड़ी है कि सब जगह नहीं भेजी जा सकती है और अनइमैजिनेटिव आफिसर्स ऐसे है कि जहा ऐसी स्थिति है वहां भेज नही रहे है। मै ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलना चाहा, उन को फुर्सत नही थी। दूसरे रिलीफ आफिसरों से बात की। उन्होने कहा कि हम हेल्पलेस है, हमारे पास नाव नही है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कितने लाख खर्च करेंगे, यह मैं नही जानता। आज की जो स्थिति है उस में लोगों को कैसे राहत पहुचाई जाय, यह देखने की जरूरत है। सारे कुएं पानी में है, सारे ट्यूबवेल पानी मे हैं। घर पानी मे है। लोग खड़े-खडे दिन बिता रहे है। केवल जहां रेलवे लाइन है वहा लोगों ने शरण ली है और इस हालत में जब कि नीचे पानी है, ऊपर से बारिश हो रही है, क्या स्थिति होती होगी ? उन के माथे पर छप्पर नहीं है, कोई चांदनी नही है। पानी में भीगते है, खांसी बुखार होता है, कोई दवा का भी प्रबन्ध नही है क्योंकि वहां हम जा नही सकते हैं। कोई कन्वेयेंस नही है। सोनपुर से ले कर छपरा तक 30 मील की एरिया में यह बाढ़ है। 30 मील लम्बा और 8 मील चौड़ा 240 वर्ग मील क्षेत्र में ऐसी स्थिति है। ऊपर हेलीकाप्टर या दूसरे हवाई जहाज से जा कर उसे देख सकते हैं। आज 12-14 दिन हो गए, लेकिन पानी निकलने का नाम नही लेता। नेशनल हाई वे पर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़को पर चार फुट पांच फुट पानी है। लोग जांय कैसे ? कोई सवारी जा नहीं सकती है। मैं तो नाव ले कर 20-25 गांवों में गया। सैकड़ों गांवों में से केवल 20-25 गांवों में जा सका। सब जगह यही स्थिति मैं ने देखी। उन के पास खाना नहीं है। चावल और मक्का अगर उन को दिया भी जाय तो वह बनाएं कैसे ? खायं क्या ? दियासलाई नहीं है। केरासिन आयल नहीं है, नमक नहीं है। बड़ी बुरी स्थिति है। पानी पीने को नही है। वही बाढ़ का पानी पी रहे है। इम्मीडिएट जरूरत हैं कि उन को प्रिपेयर्ड फूड देना चाहिए पैकेट बना कर और वह हर घर में पहुंचाना चाहिए। आप को वालंटियर मिल सकते हैं, यदि नाव अवेलेबल हो तो उन को भेजा जा सकता है। मैं ने देखा है कि दो-दो, तीन-तीन दिन से लोग भूखों पड़े है। जो कुछ भी वह अपने घर से निकाल कर लाए वह भी बना नही सकते। और बहुतों के पास तो है नही। रबी की फसल पानी से नष्ट हो गई और खरीफ की फसल 5 फुट 6 फुट पानी के अंदर पडी है, तो कहां जाय और क्या खायें ? नुकसान तो अभी भी जब कि पानी नही निकला है, बहुत है। जिनने कच्चे मकान थे वह गिर गए और ईट के मकान है जो सीमेंटेड नही है वह पानी निकलने के बाद गिर जाएंगे। तो सवाल सैकड़ो हजारो का नहीं होगा, लाखो घरो का सवाल होगा और सारी सड़को को मरम्मत करवानी होगी सारी सड़को की मरम्मत और लाखो घरो को बनवाना कोई साधारण काम नही है। बहुत ऐसे गरीब है कि खुद बनवा नही सकते है और उन को कोई राहत मिल नही सकती है। तो उन को या तो पेड़ के नीचे जीवन बिताना होगा या खुले आसमान के नीचे बिताना होगा। बाध आप पीछे बनवाइएगा जब पानी निकल जायगा। इस वक्त तो उन को पीने का पानी और रहने के लिए कुछ तिरपाल या कोई ऐसी चीज दीजिए जिससे पानीमे वह भीग न सकें और दवा का इंतजाम होना चाहिये जिसमें खासी बुखार और जुकाम से तो न्यूमोनिया न हो जाय और उन को कोई देखने वाला न रह जाय। इस के अलावा इम्मीडिएटली फेयर प्राइस शाप्स करीब-करीब हर गांव मे या दो गांवों के बीच मे खोलिए। जिन को हम देखते हैं कि वह धनी भी हैं या घर के अच्छे है, उन का भी आज तो सब कुछ बह गया। वह पैसा दे सकते हैं, अपना जेवर बेच सकते है, खेत रेहन रख सकते हैं लेकिन अन्न कहां से लाएं ? इसलिए आप फेयर प्राइस

[श्री डी० एन० तिवारी]

शाप खोलकर उन को दो पैसा महंगा चाहे दीजिए लेकिन अन्न तो पहुंचाइए जो कि वह खा सकें। वह चैरिटी नहीं चाहते हैं। लेकिन अन्न चाहिए जो उन को मिल सके क्योंकि वह उन के पास नहीं है। गरीबों के लिए आप जितना मुफ्त में दे सकें दीजिए और बाकी बेचने का इंतजाम कीजिए। जैसे ही पानी हट जाय और मैं समझता हूं कि अगर सेजी से पानी हटेगा तो अभी एक हफ्ते से कम में नहीं हट पाएगा, तो जैसे ही पानी हट जाय तो ऐसा प्रबन्ध कीजिए कि हर एक कुएं से डिसइन्फेक्टेंट दीजिए जिस से पानी पीने से लोग बीमार न पड़ें नहीं तो बीमार पड़ेंगे तो इतने डाक्टर आप मुहैया कर नहीं सकेंगे और इतनी दवाई भी नहीं दे सकेंगे। तीसरी बात यह है कि इस विपत्ति के समय में मालगुजारी जो वसूल होती है, सरकारी अफसर माल गुजारी मांगते हैं वह तुरन्त बन्द की जाय नहीं बन्द की जायगी तो वह देंगे कहां से या तो आप उन के मवेशी खोल कर ले जाइये, खुद ही नीलाम कर लीजिये, लेकिन वह दे नहीं सकते है।

श्री पी० के० देव : लगान माफ कर दीजिए।

श्री डी० एन० तिवारी : माफ कर दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस समय कम से वसूल न करें।

तीसरी बात यह है कि जो बांध आप बनवाते हैं, उस में सफिशियेन्ट आउट-लेट नहीं होता है, अगर हैवी-रेन्ज हो जाय तो उस का पानी गांव से बाहर नहीं जा सकता, वहीं इकट्ठा हो जाता हैं। इस लिये आप ओपनिंग्ज दीजिये। हर गांव में जहां बांध हो, रोका इन्तजाम कीजिये जिस में पानी गांव में ही इकट्ठा न रह जाय गांव से बाहर हो जाय, वरना जितना बाढ़ से नुकसान नहीं होता, उस से कहीं ज्यादा इस तरह पानी इकट्ठा हो जाने से गांव का नुकसान हो जाता है, फसलों को नुकसान होता है। बांध बनाते समय आप इस बात को ध्यान में रखिये। आज आप के जो बांध बने हुए हैं, जो इन्टैक्ट हैं, उनमें स्लूइस गैट्स नहीं हैं, इसलिये इस बात का इन्तजाम करते हुए जहां-जहां जरूरत हो, बांध बनाइये।

मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं कह रहा हूं, छोटी छोटी बातें ही कह रहा हूं जिन से लोगों को राहत मिल सकती हैं। मक्के के पेड़ 6 फुट पानी में डूबे हुए हैं, मवेशी कहां से खायेगा। जो कुछ उन के पास था, वह गल-सड़ गया, सिर्फ पेड़-पत्ते काट-काट कर खिलाते हैं। इस लिये आप जल्द से जल्द उन के लिये फोडर का इन्तजाम कीजिये, चाहे आप को बाहर से मंगवा कर देना पड़े, लेकिन यह व्यवस्था फौरन होनी चाहिये, कुछ कर्ज के रूप में दीजिये, कुछ ऐसे ही दीजिये अन्यथा हफ्ते भर बाद पेड़ों के पत्ते भी नहीं मिलेंगे और मवेशी मरने लगेंगे।

दूसरी बात, आगे आने वाली फसल के लिए आप अभी से प्रबन्ध कीजिये। अगर आज से प्रबन्ध नहीं हो सकेगा, तो किसानों को समय पर बीज नहीं मिल सकेगा। हम ने बराबर देखा है कि बीज यहां से देर करके भेजा जाता है, और बोने का समय बीत जाने के बाद उन को मिलता है। जब उन को समय पर बीज नहीं मिलेगा तो वे कहां से बोयेंगे। इस लिये इस का प्रबन्ध पहले से होना चाहिये। आप को मालूम है कि अनटाइमली रेन से उन का सारा बीज बरबाद हो गया है, सड़ा बीज भी यदि ये बोना चाहें तो वह भी उन के पास नहीं है। इस लिये बीज का इंतजाम, फर्टिलाइजर का इंतजाम, पहले से होना चाहिये और कर्ज के रूप में उन को दिया जाना चाहिये, फसल होने के बाद आप उसको वसूल कर लीजिये, लेकिन यदि आज आप उस का पैसा मांगेंगे तो वे दे नहीं सकेंगे।

*SHRI M. RAJANGAM (Dindigul) : Mr. Chairman, Sir, the twin spectres of floods and drought haunting the whole country are under discussion in this House and I am grateful to you for giving me an opportunity to participate in the debate.

*The original speech was delivered in Tamil.

You are aware, Sir, that no State in our country is an exception to the vicissitude of either floods or drought. Many States this year have been afflicted by ravaging floods. In the whole country nearly 13 crores of people have been uprooted by the marauding floods. So far as our country is concerned, floods are not a bolt from the blue ; it is a regular recurring feature every year. The annual loss from floods is about Rs. 100 crores. This year the total loss on account of floods is estimated to be Rs. 275 crores. The loss of agricultural crops this year due to floods is unprecedented in the history of our country. The only redeeming feature in such a gloomy atmosphere is that the Ministry of Irrigation and Power is headed by the world-renowned and most experienced Engineer, Dr. K. L. Rao. He is our only hope in finding a permanent solution to the pernicious floods. We appeal to him to give his serious consideration to the continuing problem of catastrophic floods and to find an ever-lasting solution. We hope that he does not identify himself with the like of Congressmen and belie our expectations. We fervently believe that he will exert his utmost in redeeming the country from the scourge of floods. Many thousands of villages throughout the country have been inundated by roaring flood waters and lakhs and lakhs of our countrymen have lost their little thatched huts. The floods and drought take their toll side by side. Though we have been incessantly talking about the flood and drought havoc all these twenty-four years, it is really a sad commentary on our performance that we have not succeeded in extricating ourselves from the disastrous floods and drought.

Here, I would like to refer to the suggestion which has been made many a time both inside and outside this House. This scheme, when implemented, will absolve the Centre from the sin being Committed in Cauvery. It is the grand and magnificient scheme of linking the swelling Ganges with the placid waters of Cauvery. If this scheme is implemented in right earnest, the parts of India now pillaged by floods will be made fit for plough and the chronically drought affected areas will become fertile for cultivation. With this scheme we will be in a position to kill two birds with one stone the twin spectres of floods and drought will be done with. When this scheme is taken up, thousands of engineers will get employment besides providing job opportunities for lakhs and lakhs of people. The elusive concept of national integration will become a reality. In fact, this scheme will open up vast avenue of opportunities in many fields of our activities.

By undertaking this scheme, the unsavoury water disputes like Cauvery water dispute will automatically disappear. Whatever may be the hurdles and bottlenecks in implementing this scheme, it must be taken up right now in the interest of the nation as a whole. Even though it may not be possible for us to go whole hog with this, at least we can make a beginning by taking it up in stages. For instance, 70% to 80% waters of Godavari and Krishna in South go waste into the sea. After linking these two rivers, then we can extend our programme to connecting Vada Pennai, Palaru, Then Pennai and Cauvery with Vaigai. In the absence of such a link-up the waters of these rivers are not fully utilised. Then we can go to the next stage of connecting Narmada and Godavari and ultimately Ganges and Yamuna with Narmada. This kind of implementing this gigantic scheme in stages will lead to substantial increase in agricultural production apart from yielding manifold side benefits. The problem of floods and drought will vanish in thin air.

Now, coming to the chronic drought problem in many States, I would like to make a particular reference to such areas in Tamil Nadu. There are areas in Ramanathapuram District, in Madurai District—specially Dindigul, Tirumangalam, Usilampatti and Nilakkottai—in North Arcot District and also in Salem District, which are regular victims of chronic drought. No doubt, the State Government of Tamil Nadu has been spending most of its resources in alleviating the sufferings of the people inhabiting these areas. I have specifically referred to these areas because they are in need of succour from the Centre. I would appeal to the hon. Minister to extend central financial assistance for these drought-stricken areas. I am sure that my appeal in the genuine cause of common people in these areas will meet with the sympathetic consideration of the Minister.

Before I conclude, I would once again refer to the imperative necessity for linking Ganges with Cauvery if we are keen to save the country from the savage grip of floods and drought.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: The time should be extended.

श्री के० डी० मालवीय (डुमारियागंज) : मेरी बात आप नोट कर लें कि बस्ती जिले में भी बाढ़ आई हुई है और वहां के लिये भी कुछ करना चाहिये तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी । . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : आप लोग एक्सटेंशन चाहते है और हमको आप लोगों की जो आज्ञा होगी उसको मानना पड़ेगा । आप लोग कितना टाइम एक्सटेंड कराना चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : कम से कम एक घंटा ।

सभापति महोदय : ठीक है, एक घंटा टाइम एक्सटेंड हो जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अगर माननीय सदस्य भाषण न देकर केवल सवाल कर लें तो फिर उसमे ज्यादा समय नही लगेगा ।

सभापति महोदय : मै माननीय सदस्यो से कहता हूं कि वे चार पांच मिनट में समाप्त कर दें लेकिन वे 13, 14 और 15 मिनट बोलकर भी संतुष्ट नहीं होते । यह मेरी डिफीकल्टी है । श्री विभूति मिश्र जी ने बहुत अच्छा सजेस्शन दिया है । अगर आप लोग अपने यहां की प्राब्लम साल्व कराना चाहते हैं तो सवाल पूछें और उसका उत्तर भी आपको ठीक से दे दिया जायेगा और इससे आपका काम हो जायेगा । दो एक मिनट और भी बोल सकते हैं । . . (**व्यवधान**) . . .

श्री एन० एन० पांडे (गोरखपुर) : समस्याओं को सुलझाने के लिये 5 मिनट का टाइम ठीक रहेगा ।

सभापति महोदय : पांच मिनट से ज्यादा न लें ।

श्री गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : आपकी तवज्जह खींचने का कौन सा तरीका है ? आप कौन सी नीति का पालन कर रहे हैं ? हमारा लिस्ट में नाम है लेकिन आप बुलाते नहीं है ।

सभापति महोदय : चेयर की नीति यही है कि हमारे सामने लिस्ट रहतो है उससे बुलाते हैं ।

श्री गंगा रेड्डी : लिस्ट भी फालो नहीं करते हैं और दो मिनट में घटी बजाते हैं ।

सभापति महोदय : पांच मिनट से कम कोई नहीं बोला है ।

श्री अनन्तराव पाटिल ।

SHRI ANANTRAO PATIL (Khed) : This year nature seems determined to put this country to a test. In some parts there are no rains, in other parts there have been heavy rains. This condition of drought and deluge has the same effect. In both cases crops have been damaged. But the division is distinct. In the northern part of the country, UP, Bihar, Bengal, Orissa, some parts of Punjab and Rajasthan, there are floods ; in south India, in Maharashtra, Mysore, Andhra and some parts of Madras, there is drought. In Kerala there have been floods. The khariff crops have been lost or damaged.

You are the Chairman of the Farming Forum. You know the plight of the agriculturist if the rains fail at the time of the sowing of the khariff crop. This year Maharashtra is in the grip of the worst famine. Man proposes, nature disposes. We got rain in Maharashtra in the first week of June and we were hoping for a good khariff crop, but after the 10th June, for sixty days now, we have had no rain. Out of 26 districts in the State, 16 are most-affected.

Eight districts have been partially affected, and there are four or five districts which lie in the Konkan ; paddy harvest was good there, but the jowar, bajra, groundnut and other crops, especially in the Marathwada region of Maharashtra which is the granary of Maharashtra have suffered. This year there was no rain ; and so no sowing, and where sowing could be done, the germination was not possi-

ble. In the eastern districts of Maharashtra, where paddy is grown, the crops have been lost this year and the western districts of Maharashtra including the district of the Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture, Shri Annasaheb P. Shinde—Ahmednagar, Sholapur, Poona and Nasik districts—have been worst affected. This year, in many of the districts of Maharashtra, there was no rain. Famine conditions exist continuously for years together in some areas; there is a chronic famine condition. There is one taluka in the Nasik district which for the last 100 years has remained famine-stricken. So, the calamity is a severe one. It has been fourfold in Maharashtra. The crops have suffered. The agriculturists have no work today. There are no operations on the farms. Agricultural labour has no work to do. So, they are to be provided with work and wages, so that they will be able to purchase foodgrains and subsist on them.

For the cattle also, there is no fodder; because of the failure of rains, there was no fodder for them available. The next greatest calamity in Maharashtra is drinking water shortage. If you do not receive rains in August, this month, I am afraid the rabi sowing will be very much affected, and in the months of April and May, during summer, the people will suffer greatly. So, the supply of drinking water, fodder and provision of employment are a dire necessity. Already, the foodgrain prices are going up every day. The State Government is trying its level best to meet the situation. Varuna seems to be displeased this year in Maharashtra. He may be demanding some pooja with some heads of men and women, but the State Government and the people are determined not to lose a single life in Maharashtra.

We have started famine works and the work on roads which are being constructed. Percolation tanks and community wells are being dug. Work which will give relief and which gives job and employment to the able-bodied men and women in the rural areas who have no work in the agricultural sector has to be provided. But the resources or funds available with the State Government are very limited. The other day, the Minister of Agriculture gave an assurance in the other House that the Centre will be sending out a team to Maharashtra and that after the report is received, the Government will give assistance to the Maharashtra Government. We are very grateful and thankful to the Central Government and the Minister, but the time is running short. When will the study team be sent, when will they study and when will they submit the report, and what will happen to it? Already, Rs. 5 crores have been spent by the Maharashtra Government, and it has been calculated that the expenditure on famine works or relief works might exceed Rs. 12 crores to Rs. 15 crores. So, it is very necessary that funds should be made available to the State Government. It is not only the question of funds.

It is also a question of materials and machinery, blasting machinery, boring machinery for digging wells and for providing drinking water. If these are available with the Central Government, they should make them available to the State Government.

As far as fodder and foodgrains are concerned, for the procurement of fodder from other States, the Central Government should help our State. About foodgrains, we were happy to know that this country has become self-sufficient in the matter of food and need not depend on others. But I am afraid what will happen next year because of the drought and famine and floods and scarcity of rain. We would have to meet the needs from abroad. We do not know. Of course, the Food Corporation of India and the Central Government will supply food to the State Government since they have got ample stock with them. But about the prices, they should give us some relief, especially for the famine-stricken areas.

I do not want to take more time of the House. But I would only urge upon the Minister, especially Dr. Rao, who is the Minister in charge or irrigation and power, to attend to our needs. He has mentioned some short-term arrangement to solve the issue, but what about the long-term arrangement? What is the arrangement for irrigation, major, minor and medium, in those districts which are permanently famine-stricken, which come under real shadow? We have got irrigation only to the tune of 7 or 8 per cent in Maharashtra. Even if you make all the water available, it will come to only 18 to 20 per cent. So, in areas where there are no possibilities of major irrigation projects, minor and medium irrigation projects should be taken up and

[Shri Anant Rao Patil]

they should be given priority and necessary funds.

16.00 hrs.

I again request the hon. Minister of Agriculture to send a study team as soon as possible and ask the Central Government who are trying their level best and fighting the famine to the best of their ability.

श्री एन० एन० पांडे : चेयरमैन महोदय, मुझे दो सूबों, उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । माननीय मंत्री जी और माननीया प्रधान मंत्री के साथ बाढ़ की लीला देखी और जिस तरह से आज आदमी जिन्दगी गुजर कर रहे हैं उसको अपनी आंखों से देखा है । आज जैसी स्थिति है उसके लिये हमें मुस्तकिल इंतजाम करना पड़ेगा ।

शौर्ट टर्म पौलिसी के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा । बाढ़ खत्म हो जायगी उसके बाद रबी की जो बुवाई है, लोगों के लिये दवा, पानी का इन्तजाम है, बैलों में जो बीमारी पैदा होगी, इन सब का इन्तजाम तो आप करेंगे ही, लेकिन यह जो 22 सूबों में बाढ़ आयी है और तीन ऐसे सूबे हैं, जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा, महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश, ये सूखे से परेशान हैं, लेकिन यह जो बाढ़ की विभीषिका आये साल देखने को मिलती है इनके लिये जब तक आप नदियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक नदी घाटी योजना नहीं बनायेंगे, जब तक आल इंडिया लेविल पर इसका इंतजाम नहीं करेंगे तब तक हम बाढ़ की विभीषिका को नहीं रोक सकते ।

मैं अभी विदेश गया था मैंने हंगरी को देखा, वहां बुडा और पेस्ट के बीच में डैन्यूब नदी को बांधा गया और वहां पर बुडापेस्ट बड़ा सुन्दर शहर बसा हुआ है । इसी प्रकार चीन की जो भयावह नदी थी उसको बांधा जा सकता है लेकिन गंगा नदी, जिसको हर हिन्दू पवित्र मानता है, उसका जल पीता है, और मरने के बाद भी उसमें अस्थि विसर्जन किया जाता है, ऐसी पवित्र नदी को इस भूभाग की तरक्की के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सका है ।

आज बाढ़ क्यों आ रही है । सौ साल में ऐसी बाढ़ नहीं आयी । मैंने पटना, मुंगेर और खगरिया को देखा, चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है । बरौनी में जो 150 करोड़ रुपये की रिफाइनरी है, जहां पर पावर स्टेशन हैं, गुप्ता बांध है, डैमेज हो रहा है । इसी तरह से छितौनी से खड्डा के बीच में जो छोटी लाइन है, जिसको मंत्री महोदय ने स्वयं देखा है, बड़ी गंडक ने धारा बदल दी है । आज उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद, नवासी और मधुबनी के 13 ब्लाकों में से 11 ब्लाक जलप्लावित हो गये हैं । आदमी कहां रह रहे हैं ? पिपरासी बांध को काट कर आदमी गुजर रहे हैं, जिनके लिये खाना, कपड़ा, मकान और रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है । वहां लोग आज आदमी की जिन्दगी नहीं बल्कि जानवर की जिन्दगी बसर कर रहे हैं । स्वराज्य प्राप्त हुये इतने दिन हो गये लेकिन इस समस्या के निवारण के लिये कोई मुस्तकिल स्कीम आज तक लागू नहीं की गयी ।

सभापति महोदय, मैं आप की अनुमति से कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार ने सब सूबों को मिला कर, जहां बाढ़ आयी, ओला पड़ा कितना रुपया दिया, यह इन आंकड़ों से प्रकट होगा । 1965-66 में 8.15 करोड़ रुपया सूबों को दिया गया । 1966-67 में 82 करोड़ रु० दिया गया, 1967-68 में 75.50 करोड़ रु० दिया गया और 1968-69 में 150.50 करोड़ रु० दिया गया । इस सब धन-राशि को जोड़ा जाय तो इन सालों में फ्लड निवारण और रिलीफ के लिये केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को 394.26 करोड़ रु० दिया आज अरबों रु० की बरबादी हुई है । हमें बैठ कर सोचना चाहिये कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या मुस्तकिल हल हो सकता है ।

आप को याद होगा कि हमारे यहां जब बाढ़ आयी थी तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से कहा था कि खुदा बदतमीज हो गया है। मेरी राय में खुदा नहीं, इंसान बदतमीज हो गया है और वह इस लिये कि हिमालय जो हमारी हिफाजत करता था, वहां से पानी के कारण और चट्टानों के टूटने से नदियों में बाढ़ आ रही है। आज जब कि दुनिया में नाना प्रकार के अन्वेषण हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में हम कोई अन्वेषण नहीं कर रहे हैं कि कैसे इस पानी को कंट्रोल किया जाय। यू० पी० में ऊपर पहाड़ से फूट कर नदी उत्तर प्रदेश में आयी, बिहार में उसने समतल जमीन पायी जिसके कारण वह नदी भयंकर लीला करती है, और बंगाल में कलकत्ता जाते समय उसकी विनाश लीला और भी अधिक बढ़ जाती है।

समय कम है इसलिये अधिक न कह कर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि नदी घाटी योजना बनाई जाय, और सेंट्रल फ्लड बोर्ड बनाया जाय जो सारे सूबों को पैसा न दे बल्कि खुद खर्च करे, स्कीम बनाये और खुद ही उनको इम्प्लीमेंट करे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक प्रदेश की सरकारों के मान का यह काम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के कथनानुसार वहां 200 करोड़ रु० का नुकसान हुआ है। बिहार के मंत्री के अनुसार वहां 140 करोड़ रु० का नुकसान हुआ है। सारी क्रोप डैमेज हो गयी है, वहां खाने का इंतजाम नहीं है। जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा बाढ़ में घिरे लोगों के लिये हमको फूड पैकेट्स देने चाहिए, उनके लिये पीने के पानी का इंतजाम करना चाहिये। छोटी और बड़ी स्कीमों को बाढ़ रोकने के लिये चालू करना चाहिये। यदि हम स्थिति का ठीक से मुकाबला नहीं करेंगे तो देश में भुखमरी आने वाली है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते।

• •

बाढ़ आयी, उसके पहले ड्राउट आया, उसके पहले ओला पड़ा। केन्द्रीय सरकार को यू० एन० ओ० में कहना चाहिये कि इस तरह के अनुसंधानों को बन्द किया जाय तो मौसम में गड़बड़ियां पैदा करते हैं। तभी जा कर इंसानियत की पूजा हो सकती है, सेवा हो सकती है और हम समाजवादी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

SHRI K. RAMAKRISHNA REDDY (Nalgonda) : Sir, the whole of Telengana and Rayalaseema areas of Andhra Pradesh are under drought and famine conditions; not only that, even some other districts of Andhra Pradesh like Vizag are under drought. No doubt in the early days of May some rains were there and so sowing has taken place with regard to kharif crop and expecting more rains in future with the assistance of well water transplantation had been done. Then, to the utter disappointment of the farmers, there were no rains afterwards. The standing crops have withered and famine and drought conditions prevail in that area. There is no water available even in the wells either for irrigation or for drinking purposes. Special attention has to be paid to this aspect of the problem. Andhra Pradesh Government have requested the Central Government to grant them Rs. 10 crores for relief work. I hope Government of India will take the necessary steps in this regard.

Every year there is drought in Telengana and Rayalaseema areas. So, some permanent measures should be taken to prevent such conditions. I trust the Government of India will take immediate steps like sending a Central team to assess the situation, and to give Rs. 10 crores as the first instalment for undertaking immediate relief works in Rayalaseema and Telengana areas. Assistance is required not only in cash but also in kind.

Because of the drought conditions the question of exporting rice from Andhra Pradesh should not arise at this juncture. Foodgrains should be supplied through fair price shops in Telengana and Rayalaseema area, wherever it is needed. There should be drastic steps against the export of rice from Andhra Pradesh. Otherwise, the existing stocks of

[Shri K. Ramakrishna Reddy]

rice would be exported and famine conditions will continue to prevail in those areas. So, in the end I would request the Minister of Agriculture to give special attention to Telengana and Rayalaseema areas of Andhra Pradesh and do the needful in this connection.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Sir, for the last so many years I have had the privilege of participating in this debate on flood and drought whenever it comes every year. Just as we celeberate the day of our independence, it has become a ritual with us to celebrate the day of mourning, usually in the month of August, when the Parliament is in session and the country is in floods.

During the last one week in Orissa almost all the major rivers are in spate and the whole State is in the grip of a devastating flood. We had a similar flood in 1968 and also last year. Now the rivers Mahanadi, Baitarani, Brahmini, and Kharsuar and all other rivers are in floods. All the low-lying areas of Orissa are under water. Since all the major rivers are in flood the districts of Cuttak and Balasore are badly affected. As the Mahanadi is in flood the coastal areas like Puri and areas in my constituency are now facing serious difficulties and almost a million people are affected in Orissa. Another about 5 lakh acres of sanding crops have been damaged. Sir, the peculiar thing is that there were so many projects for protecting areas from floods any Baitarani and other rivers. The Bheemkund project was planned to control floods in Baitarani river. What happened to that project? The constituency of my friend Shri Arjun Sethi in Bhadrak and vast areas in Shri Avadi Das's constituency in Tajpur are severely damaged. There are areas in Cuttack district and in other places of Orissa where for six months the people and the area remain submerged in flood water and for another six months they suffer from acute drought. Alternately there are drought and floods—that is how our Orissa is suffering from. Sir, I think that all the major flood control projects if they have come for approval of the Central Government should be cleared. Just one month before in this very House I had brought to the notice of the hon. Minister that so far as Orissa is concerned no major flood control scheme on these very rivers which are in spate today have been forthcoming. Excepting the Hirakud Dam in the earlier years, no other major flood control scheme has been implemented during the Second, Third and Fourth Plans.

What happened to Tikerpada project, to Gania barrage scheme and to Bheemkund project? Has the State Government sent any such scheme for clearance. If so, that should be cleared also.

Now, I want to touch only specific points and I hope the Minister will look into them. Last year, in 1970, the hon. Minister told us there is going to be a revolving fund for flood control. I thought the fund is revolving, but in 1971 I do not know whether the fund is revolving outward or inward. Give us some light. What happened to this fund? The Minister also said that we are preparing a massive flood control scheme for the entire country. Where is that scheme? At least we should know something about that scheme. The Minister told us in this House that an additional 50% of the area would come under drought and flood control. Therefore, I submit that more and more areas should be brought under flood and drought control. If there is drought in the western part there is excessive rain in the eastern part. Why don't you divert water from the Ganges and other eastern rivers to those areas where there is scarcity?

One or two more points about my own constituency particularly in reference to the areas near about Chilka, and the hon. Minister is also seized of the matter. Now, take for instance the National Highway No. 5. It was completely damaged and there were more than 40 breaches during the worst 1968 floods and the Government of India gave enough money to repair all these damages. What happened to that money? How was that money spent? I cite one particular instance here. One furlong away from Balugau a breach occurred in the National Highway then. It was a causeway. The Government of India approved a scheme for constructing a bridge for allowing discharge of flood water to Chilka. But what happened? The State Government only constructed the road thereby blocking the discharge of flood water from an area of 3,000 acres of best paddy land. That

area now remains submerged in rain water. Whenever you prepare any scheme for a particular purpose something different comes out. Supposing an ass is born in an automobile garage it never becomes a baby automobile. It remains an ass and the plan approved by the Ministry of Transport of the Government of India for this breach at that particular point of the national highway No. 5 was not implemented. The areas are submerged and the people are suffering. So the mouths of the rivers Baitarni, Salandi and Chilka lake and all those rivers which drain themselves into the sea in Orissa have been silted up and they need dredging for quick discharge of flood water, so that water-logging is not there. Three to four thousand acres of area in the Bhusandapur refugee colony near Chilka are completely waterlogged. There is no arrangement for quick discharge of flood water in the Block No. 1 of this colony. They remain waterlogged for months.

If you work out the ratio of flood prevention to flood relief, it comes to 1 : 5. If you spend Rs. 11 crores on flood prevention, you spend Rs. 25 crores on flood relief. This way things cannot go on. Why don't you reverse it.

These are the problems before the Government. There must be a comprehensive scheme at least for the coming five years. You phase out a programme of Rs. 400 crores or Rs. 500 crores to prevent completely the floods in Brahmaputra, Ganga, Mahanadi etc. Divert some water, if possible, from north India to Cauveri in South India, which is suffering from drought. We have got enough of water to give to Shri Shivappa who is crying for water.

I know, the Minister is seized of the matter and he must be taking into consideration all these things. At least for Orissa I must plead before him. The Ministry has admitted that the five States in India which are the most affected by floods are Bihar, Orissa, West Bengal, Assam and Uttar Pradesh. The annual loss caused by floods sometimes comes to Rs. 15 crores or Rs. 16 crores. It cannot be continued like this. At least when we come here for the next session there must be a plan or scheme for the coming 8 or 10 years so that we can see that more and more areas are brought under flood control schemes and there is no drought and flood at least in another period of 7 or 8 years.

सभापति महोदय : श्री पी० के० देव ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : सभापति महोदय, पार्टी की ओर से जो नाम आये हैं, आप उन सदस्यों को तो बुला रहे हैं, लेकिन यह चर्चा उठाने के लिये जिन सदस्यो ने अपने नाम दिये हैं, उनको भी समय दिया जाना चाहिये ।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : सभापति महोदय, जो फ्लड-एफेक्टिड एरियाज है, वहां के सदस्यों को समय मिलना चाहिये ।

श्री तारकेश्वर पांडे (सलेमपुर) : सभापति महोदय, जिन सदस्यों ने यह चर्चा उठाने के लिये अपने नाम दिये है, उनको पहले अवसर दिया जाना चाहिये । क्या अब यह परम्परा बदल रही है ?

सभापति महोदय : यदि समय होगा, तो माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा । श्री पी० के० देव ।

SHRI P. K. DEO : Mr. Chairman, I have carefully gone through the Statement of the Minister of Irrigation and Power which has placed on the Table of the House on the 3rd August, 1971. I am vitally concerned with my States ; so, I have gone through the portion regarding Orissa and I find that the statement is an understatement. It has absolutely no relevance to the reality because today I verified from the Government of Orissa sources by telephone and would like to bring to your notice that since the 3rd July Mahanadi, Baitarani, Subarnarekha and Budabalanga have been in spate and the districts of Cuttack, Balasore, Dhenkanal and Keonjhar are being affected by floods. 4 lakhs acres of land have been submerged and 6 lakhs of people have been affected. 1,000 houses have already collapsed and many are about to collapse. 11 human lives have been lost and many more cattle. There have been breaches on the flood protection embankments at Panikoili on the Brahmani, Rambapur on the Mahanadi and Ringbandh in the Aul area.

In this regard I would also like to point out the magnitude of the problem so far as the

[Shri P. K. Deo]

Sabarnarekha is concerned It is a border river between West Bengal and Orissa in the upper reaches but in the lower reaches it enters into the State of Orissa.

Now, there has been a joint endeavour between the West Bengal and Orissa Governments to provide flood protection embankment in the upper reaches on both side of the river. But that will not solve the problem. If you divert water which inundates West Bengal to the lower reaches, the casualty would be Orissa. So, I would like to submit that the Government of India should give clearance to an estimate of 10.48 crores for the construction of an embankment on the Subarnarekha river even though they have already sanctioned Rs. 120 lakhs for West Bengal—I do not know under what consideration—but due consideration should be given to the State of Orissa in this regard.

I do not want to cross swords with my hon. friend Shri Panigrahi. But I would like to point out, and he should bear in mind, that any idea of Tikarpara Dam should be shelved in the cold storage once and for all. We do not want the submergence of 2000 sq. miles of up-lands of Orissa. We do not want the interests of the people of up-lands of Orissa to be sacrificed at the altar of the coastal people. Only on the bogi of saving the coastal districts, no question of submergence of the hilly areas should be taken into consideration.

I support the demand for Bhimkhand and I think, sufficient steps should be taken in this regard.

In 1969-70, there was a flood of this magnitude for which the Central assistance was given to the tune of Rs. 3 crores and odd. This time, the magnitude of flood has been much more and at least Rs 4 crores Central assistance should be given to the State of Orissa to rehabilitate those persons who have been uprooted by this flood.

Lastly, I would like to submit about the reaction of the Ministry of Agriculture on the flood situation. I cannot understand it. Even though they say that 10 per cent of the crop area has been damaged, still they hope to attain the target of 130 million tonnes of foodgrains by 1971-72. It cannot be anything but astrology and moon-shine. We hope, by next year, we will become self-reliant so far as food is concerned. We will not have to depend on PL-480 Fund. But the large influx of refugees and the flood situation have completely upset the economy of the country. Due consideration should be given to this aspect also.

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

क्या यह सही है कि भूकम्प के बाद गंगा आदि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों का बैड ऊंचा हो गया है, इसलिए उत्तर बिहार की नदियों मे पानी के बहाव मे रुकावट पैदा हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लड आ जाता है ?

क्या यह सही है कि लैंड हंगर के कारण लोगों ने पानी के बहाव के सब रास्तो और चैनल्ज को खेती मे सम्मिलित कर लिया है, जिसका नतीजा यह है कि वर्षा के कारण नदी के पानी का बहाव रुक-जाता है और फ्लड हो जाता है ?

क्या यह सही है कि जो नये नये प्रोजेक्टस बनाये गये है, उनके कारण पानी के बहाव का इन्तजाम नही है, इसलिए पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण बाढ़ आ जाती है और लोगो के घर और सम्पत्ति नष्ट हो जाती है ?

सरकार को इस बारे में कोई लाग-टर्म प्लान बनाना चाहिए। उसको टेम्पोरेरी तौर पर काम नही करना चाहिए। बिहार मे पहले जब बाढ़ आती थी, तो गांधीजी ने कहा था कि यह अंग्रेजी राज के कारण, गुलामी के कारण है ; जब देश स्वाधीन हो जायेगा, तो बिहार मे बाढ़ नहीं आयेगी। चौबीस साल की स्वाधीनता के बाद भी बिहार में बाढ़ आई है और एक भंयकर बाढ़ आई है। पटना, खगरिया, मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा, चम्पारन, सारन और आरा जिले बाढ़ से सबसे अधिक

प्रभावित हैं । मंत्री महोदय बाढ़ के सम्बन्ध में कोई लांग-टर्म प्लान बनायें, क्योंकि पानी तो आयेगा, बारिश होगी ही, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है । इसलिए ऐसा कोई प्लान हो कि लोगों की सुरक्षा बाढ़ से हो सके । मुझे इतना ही कहना है ।

*SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : Mr. Chairman, Sir, the conditions in our country today are frightening. All over the country, Nature has unleashed its fury of deluge and drought and seems to be performing its dance of destruction. The country is caught between the millstones of drought and floods. Added to these natural calamities, Sir, the man-made blunders in the shape of refugees are playing havoc with our economy.

In the Northern States of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab and Orissa thousands of acres of fertile lands have been submerged by flood waters. The sufferings of the people have been aggravated by the loss of their hearths and homes, their cattle and the standing crops.

While it is so in North, the picture in South is entirely its opposite. States like Andhra Pradesh and Mysore are in the grip of severe drought.

**It is really unprecedented in the animals of Andhra Pradesh that twenty one districts have been affected. As our friend speaking for Maharashtra has said, the same conditions prevail in Andhra also. It is very unfortunate that during the months of June and July the rainfall was much below the normal with the result that in most part of the area, whether it is dry or irrigated, sowing has not been done. Not even transplantation has been done. Dr. K. L.Rao who comes from the richest district, the Krishna district, will bear testimony to the fact that even the Krishna district which has the advantage of the Krishna Barrage is adversely affected. The upland taluks of Krishna as well as other areas are very adversely affected. Never has this happened. Much more so, this Staes had the misfortune of having cyclones during the years 1968-69 and 1969-70.

16.33 hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair.*]

Andhra which is considered to be the granary of the country is going to face a very great calamity. In addition to this, in the Telengana and Rayalaseema areas where tank irrigation is done on an extensive scale, not even a drop of water is available in any of these irrigation tanks. Not only that, in small irrigation wells where three or four acres of land are being irrigated, water is drying up and ere long, not a drop of water will be left in them for irrigation.

Sir, only yesterday, all the M. Ps belonging to Andhra Pradesh met the Prime Minister and submitted to her a memorandum explaining the great calamity that has visited Andhra Pradesh. I would only want to impress upon the hon. Irrigation Minister as the Minister for Food & Agriculture and I am happy that Shri Fakhruddin Ali Ahmed also is here.

There should be a long-term approach to all these problems. This has become almost an annual ritual or recurrence ; every time, every year, we sit and devote some time in the Lok Sabha about the floods and drought. It is not humanly impossible and not within the capacity of the Government to see certain things and have a long-range plan of having certain measures taken so as to avoid repetition of such natural calamities year after year ?

The problems of drought affected areas are different. In flood affected areas at least it is a sort of temporary phase, but in drought affected areas, drinking water is also a great problem. We have to go for miles together even in normal times. For instance in the districts of Telengana and Rayalaseema even in normal times we have to go miles together to get a pot of water. This is the situation that is prevailing there. The measures so far taken are not adequate enough and Government should think in terms of having a long-range plan so as to avert these natural calamities.

What are the things to be done ? Certain flood protection measures are being taken. but in this regard, much more attention has got to be given. I am very glad to associate myself

*The Original speech was delivered in Telugu.

**From here the Member Spoke in English

[Shri P. Venkatasubbaiah]

with the sentiments expressed by my hon. friend the DMK Member.

He mentioned about the linking of the Cauvery with the Ganga. That was a project envisaged long time back by Sir C. P. Ramaswami Ayyar and Sir Henry Cotton. My hon. friend Mr. Shyamnandan Misra, I hope, will be very happy to divert some water of the Ganga from Patna to Cauvery. This will not only help us to have real integration, but also supply water to the most wanted areas, and as I have already stated in my previous speech, that will also be a sort of job-organisation programme, thousands and lakhs of technicians will be involved in this and I hope the hon. Minister will take up this project. I am glad that the Planning Commission has approved this scheme. I hope that the survey and the other preliminary work will be started almost immediately.

Coming to the drought affected areas, I would only say that we have requested the Prime Minister and I am also making this request on the floor of the House to the hon. Minister, that an *ad-hoc* financial assistance of Rs. 10 crores must be made available to the Government of Andhra Pradesh to carry on the relief measures There is scarcity of fodder. There is scarcity of drinking water. Transplantation has not taken place. I do not know what is going to happen to the overall food production in our country. Another important factor is about exploration of under-ground water.

In the areas of Rayalaseema rainfall is scanty, it is only 15 inches to 20 inches. There are vast potentialities for the exploration of underground water. Government should provide necessary machineries like rigs to go into action immediately, to see and take advantage of the situation, and to provide this long-term measure of digging wells by rigs, provide fodder banks and also open fair price shops. About this my hon. friend, speaking on the situation in Maharashtra, has already explained. So I need not go into it in detail.

There is another factor which I would like to bring to the notice of the hon. Minister. There are some irrigation and power projects which are lagging behind for want of financial assistance. here are three major projects in Andhra Pradesh, two irrigation and one power project. They are : The Nagarjunasagar project, Pochampad project and Srisailam Hydro electric project. Government should take action immediately and provide additional funds, even if they are outside the Plan, to see that they are completed in time. It will afford a permanent relief to the famine-affected areas.

Also, Government should think in terms of constituting a Famine-affected Areas Development Board as in the case of desert developments. Government has already identified the backward areas and famine affected areas in our country. Special attention must be given to these areas. That can only be made by constituting a statutory body to envisage long term plan, so as to see that steps are taken to eradicate famine.

In areas like Rayalaseema and Telengana and the coastal districts, there must be a sort of long-term plan to see that under-ground water is explored and made available to the agriculturists. We should see that large-scale unemployment is not to take place. If there is drought, there is large-scale unemployment. Lakhs of agricultural labourers, marginal farmers etc. will be thrown out of employment. Some work has to be provided to them so that there may not be any sort of unrest and during scarcity more than a crore of population gets affected by this natural calamity of drought, in Andhra.

All these factors must be taken into consideration. I also plead with the Central Government that they must depute a team immediately to assess the situation there. I am told that the Andhra Pradesh Government have already sent a detailed report to the Central Government. I would only request the hon. Minister of Agriculture to see that the Central team is deputed immediately, and pending the overall assessment and the assistance that has to be given to the State, as I had requested earlier, a sum of Rs. 10 crores relief may be given to the Andhra Pradesh Government. I would once again request Dr. K. L. Rao and Shri F. A. Ahmed to put their heads together and see that a long-term plan is evolved so that these famine-affected areas are well-protected and taken proper care of so that they will not be subject to recurring famine.

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगूसराय) : सभापति जी, मैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से आता हूं और मेरा क्षेत्र आज बड़ी गहरी मुसीबत में है—ऐसी मुसीबत जिसका सामना हमारे क्षेत्र की ही बात क्यों, सारे बिहार ने शायद ही कभी किया था ।

अगर आप बाढ़, सूखा और बंगला देश से आए हुए शरणार्थियों को ले लें तो आज लगता है कि सारे देश में करीब 45 से 48 प्रतिशत जनता शरणार्थी के रूप में हमारी मदद, सहायता तथा राहत के लिए खड़ी है ।

बाढ़ के क्षेत्र से जो खास कर आते है, उनको तो ऐसा मालूम हो रहा है कि यह जख्म नासूर हो गया है, इसका कोई इलाज होगा या नहीं होगा ? अब इसकी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है ।

हम तो ऐसी हालत में आ गये हैं कि हम कह सकते हैं "तुम अच्छा कर नही सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता" कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है.....

सभापति महोदय : आप अच्छे क्यों नहीं होते ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्योंकि ऐसे ही मसीहा मिले हैं जो इसका मुकम्मिल इलाज कर ही नहीं पाते हैं ।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : आप अच्छे होना ही नहीं चाहते हैं ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : सभापति जी, मैने दो दिन हुआ इसी सदन में कहा था कि सरकार अगर व्यवस्थित रूप से इस बार के बजट को चलाना चाहती है तो उसको एक पूरक बजट यहां पर लाना चाहिये था । जब 200 करोड़ रुपये की मांग सरकार से शरणार्थियों के लिये यहां पर रखी, मैंने उसी-दम निवेदन किया था, इससे कम धनराशि आपको बाढ़ और सूखा ग्रस्त लोगों के राहत के लिये नहीं रखनी होगी। अगर सरकार ने ऐसा किया होता तो हमारे बजट में जो बहुत कुछ दुर्व्यवस्था आने वाली है, वह न आती और एक व्यवस्थित रूप से हमारा आर्थिक कार्य-क्रम चलता ।

आप देखिये—जब बाढ़ और सूखा दोनों के आकार-प्रकार की बात यहां पर आई तो ऐसा लगा कि कम से कम इसके लिये 300 करोड़ रुपये की जरूरत होगी इस विपत्ति से ग्रस्त लोगों की मदद के लिये । सिर्फ बिहार की राहत के लिये बिहार सरकार ने 68 करोड़ रुपये की मांग की है । लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 100 करोड़ रुपये से कम में बिहार का काम चलने वाला नहीं है और इसके लिये बिहार सरकार की इतनी ताकत नहीं हैं कि वह स्वयं इसको कर सके । जहां तक मैं देख रहा हूं, बिहार में करीब डेढ़-करोड़ व्यक्ति आज बाढ़ से ग्रस्त हैं.....

श्री डी० एन० तिवारी : 2 करोड़ हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : तिवारी जी कहते हैं कि दो करोड हैं । 217 सामुदायिक विकास क्षेत्र है जिनमें इस समय बाढ़ की विभीषिका आई हुई है ; आक्रान्त मवेशियों की संख्या तो अगणित है । उनकी मदद के लिये आज चारे की जरूरत है, जो बिहार में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रबी की फसल खत्म हुई, भदई की फसल खत्म हुई । इसलिये उनके चारे का इन्तजाम हम अपने यहां से नहीं कर सकते । जब तक वैगन्ज का इन्तजाम न हो और बाहर से, पंजाब वगैरह से चारा नहीं भेजेंगे, बेशुमार मवेशी हमारे यहां आगे मरने वाले हैं । अभी जैसा कहा गया—कई सौ आदमी मर गये हैं, सौ से दो सौ आदमियों के मरने की रिपोर्ट तो छप चुकी है ।

इस बार की बाढ़ की एक विशेष बात यह है कि जब कभी बिहार में बाढ़ आती थी तो भादों में आती थी, लेकिन इस बार तो सावन में ही आ गई और अभी भी आकाश फटकर बरसने वाला है बरसने वाले नक्षत्र बाकी हैं। हम तो आगे के लिये आतंकित हैं कि क्या होने वाला है ?

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

सावन में बाढ़ आ गई, भादों अभी बाकी है और अभी भी बड़े-बड़े नक्षत्र, भीषण नक्षत्र बाकी हैं—इसलिये स्वभावतः हम आतंकित हैं।

प्रधान मंत्री जी और इस विभाग से सम्बन्धित मंत्री महोदय ने विमान से उन क्षेत्रों का दौरा किया है। विमान देखकर वहां के लोगों को कुछ राहत तो मिली होगी, कुछ तस्कीन भी मिली होगी, लेकिन कोई ठोस सहायता उनकी नहीं हो पाई है। मुझे मालूम नहीं—प्रधान मंत्री जी का जो कोष है—सहायता कोष—उससे भी बिहार के लोगों की कुछ मदद हो पाई या नहीं। ऐसे अवसरों पर प्रधान मंत्री जी के कोष से कुछ मदद मिल जाया करती थी।

अब मैं यह कहना चाहूंगा कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, उसमें इसके लिये जो विधान किया गया है, वह बिलकुल अपर्याप्त है। अभी तक पांच करोड़ एकड़ भूमि जो बाढ़ से ग्रस्त होती थी, उसमें से सिर्फ डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि की रक्षा हो पाई है यानी 33 फीसदी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की ही रक्षा हो पाई है। और, आज तक इसमें 185 करोड़ रुपये की धनराशि लगी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे 138 करोड़ रुपये-मात्र इसके लिये रखे गये हैं, इसके मायने है कि प्रतिवर्ष सिर्फ 28 करोड़ रुपया सभी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये—जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, बंगाल आदि.....

श्री रामसहाय पांडे (राजनन्दगांव): डिब्रूगढ़।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: आसाम भी इन सभी क्षेत्रों के लिये मिल पायेगा और इस 138 करोड़ रुपये में से 50 करोड़ रुपये जो पहले से आने वाली स्कीमें हैं, उनमें लग जायेंगे ऐसी हालत में नई स्कीमें तो बहुत कम ली जा सकेंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि सारे हिन्दुस्तान में यदि आप बाढ़ पर नियन्त्रण करना चाहते हैं तो आपको 138 करोड़ रुपये के बदले कम से कम 250 करोड़ रुपये इस काम के लिये रखना चाहिये।

मैं देख रहा हूं देश में आज बड़ी आर्थिक समस्यायें है, उनको ध्यान मे रखते हुए ही मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि कम से कम 250 करोड़ रुपये इसके लिये रखें।

एक और बात ऐसी है जिस पर, मैं चाहता हूं काफी जोर दिया जाय। बिहार या ऐसे क्षेत्रों के लिये जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके बारे मे ही मैने अभी कहा है, क्योंकि उनकी तफसीलात मुझे ज्यादा मालूम है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं। लेकिन इसके मायने यह नही हैं कि सूखे के बारे में बातें नही करना चाहता हूं। आज सूखे से हमारे आन्ध्र प्रदेश के लोग या महाराष्ट्र के लोग ज्यादा ग्रस्त हैं और उन्होंने उसके बारे मे पूरे विवरणों के साथ आपके सामने निवेदन किया है।

लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि बिहार में तीन-चार बातें बहुत जल्द होनी चाहिये। एक तो रेलवे मिनिस्टर साहब वैगन्ज का इन्तजाम करें, ताकि मवेशियों को चारा मिल सके। दूसरी बात—बिहार में एक मिनिस्टर जा कर कैम्प करें। कम से कम 15 दिनों के लिये वहां पर रहें और उस मिनिस्टर की पूरी शक्ति हो कि वह सब काम को कोआर्डिनेट करें, सम्बद्ध करें। जितनी भी सम्बद्ध योजनायें हैं, चाहे कृषि विभाग की हों या सिंचाई और विद्युत विभाग की हों, वह उनको पूरा करायें। आज यह स्थिति है कि वहां पर बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, शुल्क नहीं दे सकते हैं, खाने को नही है, ऐसी हालत में उनकी शिक्षा कैसे चलेगी। मैं चाहता हूं कि जो मंत्री वहां पर जा कर काम करे, वह इन सब योजनाओं को सम्बद्ध रूप से चलाये।

तीसरी बात—बिहार की कम से कम 75

से 100 करोड़ रुपये से तुरन्त सहायता की जाय।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पर आपकी करीब 200 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित हुई है, 150 करोड़ रुपया तो बरौनी में उद्योग के रूप में लेंगे और यदि आप रेल विभाग को भी शामिल कर लें तो 200 करोड़ रुपये के लागत की पूंजी विनियोजित हुई है। उसकी रक्षा के लिये आपको चाहिये कि वहां पर जो नजदीक मे तट-बाध है, उसको पुख्ता बनाइये, मजबूत बनाइये और जो नेशनल हाइ-वे नं० 31 है, जिस पर पानी चढ़ गया है, जो वहां पर पहले सड़क थी, उससे भी नीची सड़क है, उसको जल्द से जल्द ऊंचा बनाने का इन्तजाम करें।

श्री राम सहाय पांडे : मेरा एक सुझाव है—एक बाढ़ निरोध समिति बना लीजिये, जो संसद सदस्यो की हो, श्री एस० एन० मिश्र को उसका अध्यक्ष बनाया जाय और मुझ को भी आप उसमें रख लीजिये।

SHRI LILADHAR KOTOKI (Nowgong) : The problem of floods, erosion and drought has been discussed in this House year after year. Without taking much of the little time at my disposal, I suggest that it is high time Government set up a high-power Committee of MPs to see how far these problems have been troubling the country and what ways and means should be devised to effectively tackle them.

Now, it is the month of August, and so far as my State of Assam is concerned, we have yet to pass two more months and face the ordeal of floods during this monsoon also. Last year, on the 13th August, we raised a special discussion regarding the flood problems of our State. I will not repeat these things here, but I would pass on that speech, which is ready in my hand, to the Minister and request him to see how far those suggestions that we made in the House have been implemented.

It is true that the Brahmaputra Flood Control Commission has been set up. I would like to know from the Minister whether the schemes that they have drawn up for implementation during the year 1971-72, to the tune of about Rs 11 crores, have been sanctioned, because unless they are sanctioned right now, we will lose the very small period of working season which is hardly four to five months in our State. So, I will urge the Minister to expedite the sanction.

Dibrugarh town is again threatened by erosion, and this morning I received a telegram from Dhubri Grain Merchants' Association which States that from the 9th August, the town of Dhubri has been very seriously eroded and wrought a damage of the order of Rs. 30 lakhs and the people are apprehensive. So, I would request the Minister to look into the problem. I will give this telegram to the hon. Minister.

The House knows the chronic flood problems of My State, but this year, drought has affected as many as four sub-divisions. The hon. Minister of Food and Agriculture is here, and unfortunately his own constituency is very badly affected by drought and we have lost the Aus crop to the extent of 90 per cent. So far as the Sali, that is, the kharif crop is concerned, the people have not been able to start transplantation of paddy. My fear is that during the coming year and season, our State will face acute scarcity of food I am glad that the Minister of Food and Agriculture is here. He will kindly take note of this, and make preparations in advance to supply foodgrains to our State, which will be inevitably needed.

In my own constituency, there is unfortunately a missing link of about 20 km of the Brahmaputra embankment. This area is known as Mayang. Every year, it is subjected to heavy damage by floods. The hon. Minister of Irrigation and Power knows it. I would only urge upon him—in fact I am only reiterating my request—that this portion should be invariably included in the scheme under the Brahmaputra Flood Control Commission to be implemented in the coming working season.

There have been several breaches in the embankment, and again in my constituency, several areas have been very badly affected due to the breach in the embankment. We know about the damage done by normal floods, but when embankments are breached, the

[Shri Liladhar Kotoki]

damage caused to the people is tremendous, because the people are taken unawares. Therefore, this aspect of the floods due to breaches in the embankments has also to be looked into.

I know you would like me to conclude. I will conclude by urging the Minister to take into consideration another aspect of floods. That is, apart from the floods in our State, the floods in Bihar and North Bengal also affect us considerably, because apart from the misery they cause to the people affected, they affect Assam also since our heartline of transport is through Bihar and North Bengal. This year, due to the severe floods in Bihar, the train communications have been dislocated and that has been reflected by the high prices and also scarcity of essential commodities in our State of Assam. So, I would urge upon the Minister I am glad the Minister of Food and Agriculture is also present here—to take up this matter also with the Railway Minister and the Transport Minister and see that our lifeline of transport is kept free from damage and dislocation.

श्री रामदेव सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, जब इस युग में हम चन्द्रलोक पर जाने और बसने की तैयारी मे है, 20-25 सालों से आने वाली सरकार इस देश मे न तो किसी भाग को जो बाढ़ में बह रहा है उसकी व्यवस्था कर सकी है और न जो भाग सूखे की आग में जल रहा है उसको बचाने की ही कोई व्यवस्था कर सकी है। विज्ञान और टेकनोलाजी के इस युग में कोई भी सरकार अगर सीरियस रहती तो ऐसी स्थिति जो आज इस देश में पैदा हुई है, कभी नहीं होती। यह इस बात का प्रमाण है कि पिछले 25 सालों से आने वाली सरकार ने अपनी जिम्मेवारियों के साथ इस देश में मजाक किया है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा है वरना यह स्थिति इस देश में न होती। जैसा हमारे पूर्ववक्ताओं ने बताया है कि विभिन्न प्रान्तों की हालत क्या है जोकि इस समय बाढ़ की चपेट में हैं लेकिन उसमें बिहार की हालत बहुत ही खराब है। वहां पर प्रधान मन्त्री ने जाकर देखा है। हमारे इरीगेशन मन्त्री ने भी वहां जाकर देखा है कि आज कितना बड़ा भीषण अकाल वहां पर पड़ने जा रहा है। सन् 1967 में सूखे के चलते जो अकाल था उससे भयंकर अकाल बिहार में आया हुआ है। हमारी रबी की फसल खेत से खलिहान में आई लेकिन अनियमित वर्षा के चलते वह घरों में नही पहुंची बल्कि खलिहान में ही सड़ गल गई। हमारा बिहार वैसे ही अभाव का राज्य रहा है, उस पर रबी की फसल मारी गई और फिर गंगा की बाढ़ इस साल आश्चर्यजनक ढंग से चल रही है। गंगा उठती थी लेकिन दो तीन दिनों के बाद नीचे जाती थी लेकिन अभी 17 दिनों से गंगा का पानी लगातार उठता गया। 540 ब्लाकों में 200 ब्लाक पूरी तरह से प्रभावित हुए है। बक्सर से लेकर खगरिया तक और फिर साहबगंज तक जितने भी गंगा के अगल बगल इलाके है वहां पर गावो के लोग कही तो छप्पर पर है, कही ऊची जगहो पर है, कही पेड़ पर चढ़ गए है और इस तरह किसी प्रकार अपने प्राण बचा रहे है। यह स्थिति आज बिहार मे है। वहां की सरकार कितनी सीरियस सरकार है ? जब वहा पर यह हालत थी, लोग बह रहे थे, लोग छप्परों पर थे और बहुत से मवेशी और आदमी बहे जा रहे थे उस समय वहां के सारे मिनिस्टर्स दिल्ली में बैठ कर मन्त्रि मण्डल के विस्तार में लगे हुए थे। कांग्रेस प्रेसीडेन्ट की कुर्सी की लड़ाई के लिए वे लगे थे और जब प्रधान मन्त्री ने डांट दिया तब यहां से उठकर गए हैं। तो इस बार न तैयारी ही है और न सीरियसनेस ही है। आज पूरा बिहार अकाल के चुंगल में आ गया है। बिहार सरकार इसको बचा सके यह सम्भव नहीं है। इसलिए केन्द्र को पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ना चाहिए और बिहार को बचाना चाहिए। यहां पर मिश्र जी ने ठीक कहा है कि यह तो सावन का महीना है और भादों आने वाला है तब क्या हालत होगी। गंगा की बाढ़ के लिये कुछ कहना मुश्किल है। अभी वहां पर जो

नावों की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि कुछ पैसे वालों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में नावों को किराये पर ले लिया और फिर बहुत ऊंचे रेट पर चला रहे हैं। कहीं तो बकरियों को पहुंचाते हैं और कहीं दूसरे मवेशियों को पहुंचाते हैं। हमारा कहना है कि केन्द्र को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं भी इस बात को दोहराता हूं, जैसा कि मिश्र जी ने कहा है कि किसी मंत्री को वहां पर जाकर बैठना चाहिए और वहां की हालत को देखकर सेन्टर से जो कुछ सहायता मोहैया करा सकते हैं उसको कराना चाहिए। वहां की सरकार चिट्ठी लिखे और फिर यहां पर विचार हो और तब कोई देखने और जांचने के लिए जावें इस प्रकार काम चलने वाला नहीं है।

आपने घंटी बजा दी है, मैं उसका आदर करता हूं और केवल दो एक सजेशन्स देकर ही बैठ जाऊंगा।

17.00 hrs.

मैंने अभी तक स्थिति का वर्णन किया है। समय चूंकि कम है इसलिये कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

पहली बात यह कि जिन लोगों के घर गिर गये हैं उन्हें धूप और वर्षा से बचाने के लिये तिरपाल की व्यवस्था की जाय। ऐसे करीब 20 लाख लोग हैं जिनके लिए तिरपाल आदि की तात्कालिक व्यवस्था करनी चाहिये।

दूसरे यह कि बाढ़ से घिरे हुए लोगों के लिये तैयार भोजन की व्यवस्था होनी चाहिये। साथ ही मवेशियों के लिये मुफ्त चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिये रेलवे मंत्री जी को रेल के वैगन्स की व्यवस्था करनी चाहिये और चारा लाने के लिये किराये में छूट दी जानी चाहिये।

पानी हटने के बाद बीज का तत्काल प्रबन्ध कराया जाय क्योंकि किसी के घर में बीज नहीं हैं। इसीलिये बाहर से गेहूं का बीज मंगा कर लोगों को बुवाई के समय उपलब्ध कराया जाय।

जिन लोगों के घर गिरे हैं उनके लिये सस्ते दर पर लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिये, और मरम्मत की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा अनुमान है कि इन कामों के लिये 225 करोड़ रु० की जरूरत होगी जो कि लोगों को देना होगा। अगर इस स्थिति का उचित रूप से मुकाबला नहीं किया गया तो मुश्किल हो जायगी। साथ ही सरकार गैर सरकारी संस्थाओं से अपील करे कि वे सेवा कार्यों से बिहार की बचायें।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इधर ध्यान देगी और बिहार को बचायेगी।

सभापति महोदय : हर एक स्टेट के लिए एक-एक प्रतिनिधि का भाषण होना चाहिये। मेरे सामने तीन लिस्ट्स हैं—एक तो छपी हुई, दूसरी आफिशियल है और तीसरी नान-आफिशियल हैं। जिन्होने नाम भेजे हैं सब को अवसर दिया जायगा बशर्ते कि वे पेशेन्स से काम लें।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Kangra) : Sir, we are discussing the devastation caused by floods which are partly due to nature but mainly due to the inefficiency and incompetence and callousness of the department over which our good Minister presides. Even according to his own report, the floods could have been prevented had the embankments been properly put up. He says :

> "Most of the damage done in these places has been due to breaches in embankments and absence of embankments... Most of the damage that occurred this year would have been prevented if the banks had existed."

So, he concedes that basically damage to the tune of Rs. 250 crores was caused because of lack of embankments or embankments which were weak or had not been properly put up.

I would submit this is not the only instance where the inefficiency of the State Department and the Central Department has been clearly shown. There are a few other places where the inefficiency is much more.

[Shri Vikram Chand Mahajan]

In my constituency a dam is being built which is known as Pong dam. About Rs. 300 crores are being spent on this dam. They knew that a particular quantum of water would be passing through that place in the floods. They built five tunnels to take out that water, but they are not sufficient to take out even the flood water. They knew very well that floods come every year. This is not the first time that floods are coming in that region. They are there for centuries and they know it. Since they knew it they could have planned the tunnels in such a way that the tunnels would take the flood waters in their entirety. But they did not. Even though they have spent crores of rupees on that project, they did not take into account the water which would be collected during the floods. The result was that during this season the tunnel could not take the entire water collected there and so hundreds of families were put to trouble and thousands of houses were swept away. What was the compensation given to them ? One hundred rupees per family. Their houses have been swept off, the grains which they had stored had been washed away and they were given only Rs. 100. Even that has been given only in some villages and not all. I will later give the Minister the names of the villages where this has not been given.

There is another place 20 miles away from Pathankot where the railways have built a line. Every year the water collects there because the flow of flood water is stopped by the railway line. Hundreds of people of that region have represented to both Railway and Irrigation Ministry to have a bigger channel through which the entire flood water could pass so that the lands are not destroyed. The answer given by the department earlier was that they originally intended to develop this region as a fishery pond so that you can make money out of fish. But they seem to forget that thousands of acres of land which are water logged and ruined by floods have also to be taken into consideration. The entire floods could have been prevented if they had dug a bigger channel across the railway-line. This year also thousands of a acres of land have been submerged because of this. Even though I have repeatedly urged the Agriculture and Railway Ministry to attend to this, they have not paid heed to my request.

It is mentioned in the statement "hon. Members are aware that there is no method of preventing and controlling heavy downpour". It is true that water is collected by heavy downpour. If you do not kill mosquitos there would be malaria. If you do not kill rats there would be plague. If you do not kill cholera germs there would be cholera epidemic. Similarly, because of rain water will accumulate. By human effort we have to divert the waters. You have to build proper embankments, you have to punish those officers who are corrupt and blacklist those contractors who use sand instead of cement. You have to take positive and firm action instead of merely repeating that floods are created by nature.

Take the case of the Brahmaputra Flood Control Board and the officials in charge of that. We have so far spent Rs. 32 crores on that. Just make an enquiry of the assets of the engineers and officers of the Brahmaputra Control Board before they took up their present assignments and now. Kindly also check up the assets of those who have come back from that place. You will find out of these Rs. 32 crores where the money has gone. I want to ask a few questions from the hon. Minister. First, will you hold an enquiry against the contractors who built these embankments which have been destroyed due to these floods ? Second, will you hold enquiries against the engineers or officers who are reponsible for building railway line and roads which block the natural drainage and cause floods ? Third, will you first spend money on controlling the floods in the northern zone before taking up the grandiose plan of connecting Ganges with Cauveri—that would be another Mohammad Tughlak plan. Fourth, have you tried to desilt any river in India, *viz.*, Ganges, etc. so that their beds which have come up go down ? Fifth, will you hold an enquiry against the officers who planned the tunnels of Pong Dam and could not foresee that in floods the houses would be submerged and punish the responsible officers.

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक हरिजन मेम्बर को बोलने का मौका दिया है। इससे पता चलता है कि आप हरिजनों के कितने हितैषी हैं ।

बाढ़ों पर चर्चा हम अनेकों वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बाढ़ों को आने से रोका नहीं जा सका है। इन बाढ़ों के कारण हमको प्रतिवर्ष बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। फिर भी गम्भीरता के साथ कोई विशेष उपाय अभी तक इनको रोकने के नहीं किये गये हैं। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, उसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिये कि बाढ़ क्यों आती हैं। कही ऐसी बात तो नही है, कि जो जंगल है, जो पहाड़ी इलाकों से पेड है उनको काटा जा रहा है और उस कारण से पहाड़ों की मिट्टी पानी के अन्दर खिसक खिसक कर आती गई है और वह आ कर नदियों मे जमा हो गई है और उस कारण से उन नादियों की गहराई कम हो गई है ? क्या उस कारण से बाढ़ें तो ज्यादा नही आने लग गई है ? अगर यह कारण है तो इसका नतीजा यह होता है कि पानी फैल जाता है और बाढ़ें आती है। क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ताकि पहाड़ों पर पेड़ लगाये जा सकें और जो लगे हुए है उनको काटा न जाए, उनकी रक्षा की जाए। वृक्षों को काटा नहीं जाना चाहिये। अधिक से अधिक वृक्ष लगने चाहिये। यह भी एक उपाय है बाढ़ों को आने से रोकने का। इन वृक्षों की वजह से मिट्टी नदी के अन्दर नही आती है और वह वहीं रहती है। इससे हमें काफी लाभ हो सकता है। आपको एक विशेष योजना बनानी होगी ताकि नदियां गहरी हो सकें और पानी का फैलाव न हो।

कुछ साल पहले तक हमारे देश मे बड़े बड़े तालाब और कुएं हुआ करते थे। उनको हम मिटाते जा रहे है और उनके स्थान पर ट्यूबवैल लगाते जा रहे है। मैं ट्यूबवैल्ज का विरोधी नही हूं। परन्तु इन से पानी जमा नहीं होता है। जमीन से जो पानी निकलता है अगर तालाब हों तो वह उन में भरता रहता है और रुका रहता है और साल भर उन में पानी नदियों के अन्दर नहीं आ कर मिलता है और इस कारण से बाढ़ नहीं आती। तालाब अगर बनाये जायें तो छोटी सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं और पानी जमा किया जा सकता है। मै चाहता हूं इस ओर आप ध्यान दें।

इस बरसात के अन्दर मेरे अपने चुनाव क्षेत्र मे बाढ़ आ गई है, मुरैना के अन्दर बाढ़ आ गई है। मुझे यह कहने में कोई सकोच नहीं है कि ग्वालियर डिविजन के अन्दर, मुरैना मे पिछले दो तीन सौ सालो मे पहली बार बाढ़ आई है। इस बाढ़ के कारण वहा बहुत हानि हुई है। उस इलाके की उपेक्षा इसलिए की जा रही है कि वहा से विरोधी जीत कर आया है। वहां के लोगों को कोई सहायता नही दी जा रही है। एक राष्ट्रीय मार्ग बम्बई आगरा रोड बाढ़ के कारण टूट गया है। वह बन्द हो गया है। केन्द्रीय सरकार को पन्द्रह दिन तक पता नहीं चला कि वहा रास्ता बन्द हो गया है, रास्ता टूटा हुआ है। वहां के प्रतिनिधि ने आकर उस को बताया तब उसको पता लगा। राज्य सरकार इतनी निकम्मी है कि वह इसकी सूचना भी आपको नही दे पाई.....

सभापति महोदय : निकम्मी का क्या अर्थ है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : कोई काम नहीं करती है।

सभापति महोदय : आगे इस शब्द का इस्तेमाल न करें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मै उदाहरण देता हूं। बाढ आने के कई दिन बाद तक भी कोई मदद वहां के लोगों को नही पहुंचाई गई। मेरे इस क्षेत्र के डेढ़ सौ गांव पानी में डूब गए। काफी हरिजनों के मकान बह गए। लेकिन सरकार ने कोई उनको सहायता नहीं दी। उनका अनाज बह गया, फसल नष्ट हो गई लेकिन कोई सहायता नहीं की गई। मैं स्वयं वहां कलैक्टर को मिला। उन्होंने मुझे कहा कि इस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे भोपाल से कोई सहायता नहीं मिली है। वहां जब यह

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

स्थिति थी तब मेरे दल ने लोगों को काफी सहायता पहुंचाई। आज भी उस क्षेत्र में आवागमन के साधन बन्द हैं। रेल पुल डूब गए हैं। तीन चार पुलों के रास्ते डूब गए हैं। लोग नावों के द्वारा इधर से उधर आ जा रहे हैं। नावों का वे प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से भी वहां कोई सहायता नहीं मिली हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विरोधी वहां से जीत कर आए हैं। इसलिए उस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही हैं, जानबूझ कर की जा रही है। वहां जो विनाश हुआ है, उसको आप देखें और उनकी सहायता करें।

आज उस क्षेत्र में लोगों के पास अनाज खाने के लिए नहीं है। उनकी फसल नष्ट हो गई है। हरिजनों तथा दूसरे गरीब लोगों की झोंपड़ियां नष्ट हो गई हैं। उनको आपकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनको मदद पहुंचाने की व्यवस्था करें।

मुरैना जिसे में कुछ नहरें भी आपकी सरकार द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन उनका आज कोई उपयोग नहीं हो रहा है। नहरों में से पानी खेतों में जाता है और वहां आरपार दल दल बन गया है। इसकी मैंने उप मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस चीज को लिख कर भेज दूं। मैं उनको पत्र लिख चुका हूं। मैं चाहता हूं कि इस पानी का अच्छा इस्तेमाल हो, सदुपयोग हो। इससे सिंचाई ठीक प्रकार से हो ताकि लोगों को लाभ पहुंचे। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये।

अन्त में मै इतना ही कहना चाहता हूं कि इन बातों की ओर विशेष ध्यान आप दें और तत्काल मेरे क्षेत्र में राहत पहुंचाने का आप प्रबन्ध करें, राहत कार्य शुरू करें ताकि लोगों का कष्ट दूर हो, हरिजनों की मदद हो सके। मैं आशा करता हूं कि इस दुख के समय में सरकार से लोगों को अवश्य सहानुभूति और सहयोग मिलेगा।

SHRI N. SHIVAPPA (Hassan): Mr. Chairman, at the very outset I wish to point out to the concerned ministers at the Centre that the State of Mysore is under President's rule and there is no popular government there. So, if any grievance or difficulty of the people of Mysore is to be redressed, it can be done by the Central Government alone and not by anybody else. Our Irrigation Minister, Agriculture Minister and even the Industries Minister will certainly bear it in their minds not in the interest of my constituency but in the interest at least of about three crores of people of Mysore State.

I cannot describe the unfortunate condition of the people of Mysore who are now in the midst of drought and famine for the last six to seven years continuously. Famine has become our first and continuous enemy. We are so unfortunate that we have to surrender to him. There is no other alternative. It is our biggest enemy. It is a bigger enemy than anybody else.

The geographical condition of India, particularly of the Deccan plateau, is such that on one side there are the Eastern Ghats, on the other side there are the Western Ghats and in the midst of it is the Deccan Plateau with great ups and downs and with no water, no food, no irrigation facilities and no man to feed perhaps. We have not been able to put our grievances properly and so we have become a subject of mockery. Our people have not got the benefits of socialism in these 20 years nor have they got the mercy either of the Central Government or of the State Government.

All the 27 MPs of Lok Sabha and the MPs of Rajya Sabha have already visited and represented our grievance to the Prime Minister and have sought financial protection and of the Finance Minister.

Not less than Rs. 15 20 crores are to be sanctioned because, as compared to a partial drought in a Andhra which is also a part of Deccan Plateau, a partial drought in the State of Maharashtra, a partial drought in the State of Madras, the whole part of Mysore which is centrally located is fully hit by it and almost all the 18 districts of Mysore are suffering with the greatest possible acute famine. So, we are helpless; we are suffering this kind of misery in unexpressable terms. Consequently,

I appeal to the Central Government that they must do something to alleviate the sufferings of the people there.

Every year, we are wasting crores of rupees on famine relief or flood relief operations. This thing has been expressed by many hon. Members of the House. It is high time for the Government at the Centre to think of having a permanent measure. With a dynamic personality of Dr. K. L. Rao, with the coordinated effort of the Central Government, something positive and permanent should be done. The Central Government should chalk out a permanent programme, a permanent measure, to solve the problem of the 75 per cent of the rural people who are real masters behind us and to whom we have committed ourselves with our policies and programmes and to whom we have assured that by means of socialist approach, we will improve their conditions. If you really want to improve their conditions, if you really have a mind to improve their conditions, if that is our aim, we will have to do a permanent thing. There is no question of saying that we have appointed such and such a planning body which is going into the possibility of making a survey from Ganges to Cauveri. If the flood problem is to be solved, if the famine problem is to be solved, if these two enemies are to be eradicated from our sub-continent, it is high time and it is a must that the Central Government must think of a permanent measure.

We have wasted so many thousands of crores of rupees when we started an adventure in industry and all that. What after all is standing in our way to start this wonderful thing? We have got all the material resources; we have got all the water raw material to be supplied to different areas. This is to be taken up in the State of Mysore.

The hon. Minister has already assured on the floor of the House that non-scheduled rivers will be cleared and the money will be given. It is high time that they are cleared.

One more thing I will point out. The Central Government are sending out a body to survey the drought-stricken areas. As my hon. friend said, they will go there and come back with some report after sometime. In regard to the procedure to be adopted, I would like to submit one thing. They have taken "district" as a package for them. How can a district be taken as a package? Supposing in a district 5-6 taluks are suffering from drought, what will be the fate of those people? If the relief or the improvememt in industry, in irrigation and in other things, if general conditions are to be laid down, it cannot be a district package. If at all 52 districts in the whole of India are selected for improvement, it cannot be a district-like package. It should be a taluk or it should be even a smaller part as a package and they should have an eye on the difficulties of the people They should suggest it to the Government or must take a very clear view about it and see that it is recommended to the Government failing which nothing can be improved in the backward areas and our people will not tolerate this kind of thing.

There are so many projects which have been proposed to the Central Government and they are pending for sanction. It is high time that sufficient funds are allotted. Not less than Rs. 15 crores are to be sanctioned to the State of Mysore at this juncture failing which all our people will definitely come and sit before the House and the hon. Minister.

श्री शिवनाथ सिंह (झुझुनू) : सभापति महोदय, बाढ़ और सूखा दोनों ही प्रकृति के प्रकोप हैं। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हुए भी विनाशकारक है। हम प्रकृति की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उस से होने वाली हानि को कम अवश्य कर सकते हैं। यह देश बहुत बड़ा है। कुछ प्रान्तों में बाढ़ से तबाही हो रही है और कुछ प्रान्तों में सूखे से तबाही हो रही है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है, जिसको सूखे और बाढ़ दोनों से लड़ना पड़ता है। यह वहां का आये-दिन का फीचर है। सूखाग्रस्त इलाके की अपनी अलग समस्यायें हैं और बाढ़ग्रस्त इलाके की अपनी समस्यायें है। इन दोनों समस्याओं का मुकाबला एक राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा। देश को आये साल की बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई बोर्ड बनाना होगा या कोई अन्य व्यापक स्कीम बनानी होगी।

[श्री शिवनाथ सिंह]

राजस्थान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमेशा सूखे से प्रभावित रहता है। वहा की आबादी बहुत कम है, क्योंकि वहां पर पानी की समस्या है। सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि जो क्षेत्र हमेशा सूखाग्रस्त रहते है, वहां पर सूखे के प्रभाव को कुछ कम किया जाये। पहले एक डेजर्ट डेवेलपमेंट बोर्ड बना था, लेकिन आजकल वह इनएफेक्टिव है और उसके द्वारा कोई काम नही हो रहा है। इस लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक डेजर्ट डेवेलपमेंट बोर्ड बनाया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये समस्यायें बिहार, यू० पी० या राजस्थान आदि किसी एक प्रान्त के बस का रोग नही है। बाढ और सूखे को राष्ट्रीय समस्यायें मान कर उन का निराकरण करना चाहिए।

हमारे यहां जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहा पर लोगों को तीस चालीस मील से पीने का पानी लाना पड़ता है, जब कि दिल्ली और दूसरे नगरों मे फव्वारे चल रहे है। हमारे यहा पूरे का पूरा परिवार पानी लाने मे लगा रहता है। इस लिए ऐसे सुखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए रिजनल पाइप-लाइन स्कीम को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आजादी के चौबीस सालो के बाद भी हम अपने देश के किसी प्रान्त के लोगो को पीने का पानी न दे सके, यह हमारे लिए लज्जा की बात है। इस लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे कम से कम पानी की समस्या का निराकरण तो तुरन्त किया जाना चाहिए। हम ऐसे कदम उठायें, जिस से सूखे का प्रभाव कम हो सके। वर्षा नही होगी और सूखा आयेगा। प्रकृति को हम रोक नहीं सकते है। लेकिन हम सूखे की विभिषिका को कम जरूर कर सकते है। अगर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें बन जायें, तो कमी के दिनों मे हम दूसरे स्थानों से अनाज और मवेशियों के लिए फाडर ला सकते हैं। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ अधिक नहीं गया है।

सरकार ने रूरल वर्क्स प्रोग्राम की स्कीम निकाल कर अच्छा काम किया है। लेकिन इस सम्बन्ध में जिलों का सिलेक्शन जिस प्रकार किया गया है, वह आपत्तिजनक है। दूसरे प्रान्तों में भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं राजस्थान के बारे मे कहना चाहता हूं कि वहा पर जिलों के सिलेक्शन में बिल्कुल भेद-भाव बरता गया है। पता नही, यह सिलेक्शन किस आधार पर किया गया है। झुंझनु और सीकार ऐसे जिले है, जो सूखे की दृष्टि से चौथे और पाचवें नम्बर पर आते है। लेकिन उन का सिलेक्शन नही किया गया है। इसकी तुलना मे जिन जिलो मे पचास, साठ इंच सालाना वर्षा होती है, उन को इस स्कीम में शामिल कर लिया गया है। अगर इस विषय मे राजनैतिक और अन्य दृष्टिकोणों को सामने रखा जाये और जिलो का सिलेक्शन वाजिब न हो, तो दूसरे लोगों के मन मे टीस, जलन और दुख होता है। इस लिए इस योजना में जिलो को शामिल करने के लिए एक आधार होना चाहिए। जिन जिलो में वर्षा कम होती है, सूखा अधिक पडता है, आये-दिन अकाल पड़ते है, उनको इस योजना में अवश्य शामिल किया जाये। उन का शामिल न करने का कोई कारण नही है। मेरी समझ मे नहीं आता है कि उनको क्यों एक्सक्लूड किया गया है।

जो इलाके हमेशा सूखे से ग्रस्त रहते है, वहा के लोगो के लिए कम से कम यह व्यवस्था करनी चाहिए कि अकाल के समय वहां दूसरे स्थानों मे खाने-पीने के साधन जुटाये जा सकें। सूखा अकाल का जन्मदाता है और अकाल हमारे देश के कई प्रान्तों में पड़ता रहता है। राजस्थान में दस साल में से तीन साल फसल होती है, दो साल साधारण फसल होती है और पांच साल भयंकर अकाल पड़ता है। इस लिए सूखे का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न किया जाना चाहिए।

दो तीन साल पहले हमने सूखे से लड़ने के लिए एक साल में सरकारी तौर पर 100

करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये हैं। इस के अलावा जयपुर, और भरतपुर आदि में बाढ़ की स्थिति है। उन लोगों को बसाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारे प्रान्त में 85 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट किया है। हम ने कहीं और वह ओवर ड्राफ्ट का पैसा खर्च नहीं किया है। एक नैशनल कैलेमिटी को मीट करने के लिए, एक राष्ट्रीय जो संकट आया था, भयंकर अकाल का संकट था, सूखे का संकट था उस को मीट करने के लिए हम ने उस रुपये को खर्च किया है। इसलिए सेंटर को ऐसे प्रान्तों को ऐसे साधन देने चाहिए ऐसी सहूलियत देनी चाहिए जिससे कि वह प्रान्त भी दूसरे प्रान्तों के मुकाबिले में आगे आ सके और अपना विकास कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि एक राष्ट्रीय योजना बनाए डेजर्ट डेवलपमेंट की ओर उसके तहत समूचे देश के लिए विकास की योजना तैयार करें।

SHRI S. S. MOHAPATRA (Balasore) : I come from Orissa. Naturally I will try to focus attention on certain problems which have come out of the devastating floods in about 4 districts of Orissa. They are : Cuttack, Balasore, parts of Puri, Dhenkanal and Keonjhar. I would like to bring before the attention of Dr. K. L Rao that year after year we have been having devastating floods in different parts of the country. I was head of the Information Department of the Damodar Valley Corporation, which was the first multi-purpose project in India patterned on the model of the Tennessee Valley Authority. Voorduin was the maker of the Tennessee Valley Authority. The DVC project was meant to protect the floods of West Bengal and Bihar and though 8 dams were projected but only 4 dams have been completed, and thus flood protection is incomplete. Dr. K. L. Rao himself was connected with the Hirakud Dam project. He was himself the Engineer there. Year after year we see floods in the river Mahanadi and the flood have not been controlled.

There is, I understand, a National Commission on Irrigation. They have not given their interim report. Unless we take a decision to control the floods, year after year we will be seeing things like this. As there is a National Grid for Electricity, there should be a National Control of the Dams ; all the rivers should be interconnected. Therefore I ask: Why cannot the Government take up this problem and try to solve this once and for all ?

In Orissa the ravages of floods have been very much. 11 people have lost lives ; I have got a report here which I got only one hour ago from the Orissa Government. The rivers in spate are Mahanadi, Baitarani, Sabarnarekha and Budabalanga. They are in spate almost continuously. Apart from loss of 11 human lives, many cattle are reported to have been lost. A large number of embankmnents have been breached in different parts of the State. The important once are (1) Painkuti on Bramhani (2) Rambapur on Mahanadi (Cuttack) and (3) Ringbandh in Aul area. The latest position is that flood waters are receding, but even so, in many places they are above the danger level.

To solve this problem, the hon. Minister must focus his attention on the various aspects to control these devastating floods which are occurring year after year in Orissa. The present Orissa Government is not capable of solving the problem ; they are not reaching the people. They just try to blame the Government of India without trying to solve the problem themselves.

I am interested in a particular project, Sabarnarekha project. This will help not only Orissa, but West Bengal also. This Sabarnarekha project is such a project that when it is completed, 4 lakhs cusecs of water will flow between the two embankments. This is going to submerge 60,000 acres of land in Orissa area and 40,000 acres in West Bengal area. It will displace not less than one lakh of people in West Bengal and Orissa. I understand, Orissa Government is not in favour of this project. I understand, the last Government of West Bangal was also not in support of this project. I had a discussion with the hon. Minister. He assured that synchronising with this embankment he has to plan for DVC type of dams on the river Sabaranarekha in the upper and lower reaches.

I bring to his notice the concern that this plan should be put through immediately. If

[Shri S. S. Mohapatra]

it is not put through, I understand that there will be a satyagraha campaign in Orissa and West Bengal area against this embankment plan.

Simultaneously, I would also like to draw the attention of hon. Minister to the Bhimkund project which is going to control the floods on the Baitarani river.

I am bringing all these things to the notice of the hon. Minister so that he may take immediate steps. I hope he will also visit the flood-affected areas of Orissa. That has been the demand of the people there. I hope he will also recommend at least Rs. 3 crores to the flood-victims of Orissa.

श्री गंगा रेड्डी (आदिलाबाद) : खतीम मोहतरम, साले हाल हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खराब और परेशानी का है। मशरिकी इलाके मे पनाहगुजीन का सगीन मसला, मगरबी इलाके मे पाकिस्तान की तरफ से जंग की धमकी, शुमाली मशरकी इलाके मे तूफान और तुगियानी, जनूबी इलाके मे सूखा और अकाल जिस मे करोडो लोग मुतासिर हुए और हजारो करोड रुपये का माली नुकसान हुआ। आन्ध्र प्रदेश जो गल्ले का गोदाम और अन्नपूर्णा के नाम से मौसूम है आज सूखे का शिकार बना हुआ है। हर साल लाखों टन चावल देने वाला प्रदेश आज खुद मुसीबत मे आ फसा है। साले हाल का सूखा 1968-69 से ज्यादा संगीन है और कहा जाता है कि गुजिश्ता सौ सालों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा। आन्ध्र के बाज इलाकों में गुजिश्ता चार सालों से मुसलसल कहत पड़ रहा है। इस पर सितम यह कि दो बार साइक्लौन भी आ चुके। इस साल बारिश का हाल हर जिले में 15 से 40 परसेंट है। हर शख्श आसमान की तरफ देख रहा हैं। मन्दिरों और मस्जिदों में दुवाएं मांगी जा रही हैं और हर शख्श के लब पर यही आवाज है :—

किधर है जोश बदलियां रवां है सोये मयकदा।
सियाहों के हाशिये पे सुर्खियां लिए हुए॥

तैलंगाना और रायल सीमा के पूरे अजले और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊंचे मुकामात पूरी तरह मुतासिर हैं। आदिलाबाद जिले के 73 हजार एकड़ के मिनजुमले एक भी एकड़ की काश्त नहीं हुई। 8 लाख एकड़ खुश्की काश्त भी सूखे से बुरी तरह मुतासिर हुई जहां मूगफली और दालों की फसलें और मकई बिल्कुल सूख चुकी है। निजामाबाद जिले में 3 लाख एकड़ के मिनजुमले सिर्फ 60 हजार एकड़ पर काश्त हुई जो भी पानी की कमी से मुतासिर हुई है। आन्ध्र प्रदेश के पूरे तालाबो मे एक कतरा भी पानी नही आया। छोटी नदी नाले सूख चुके है। सिचाई और पीने के पानी की बावलियो मे पानी नहीं है। इस पर सितम यह कि कीड़ों और बीमारियों ने रही सही फसल को देखते देखते खत्म कर कर दिया। मवेशियो के लिए बिल्कुल चारा नही है और सैकड़ो मवेशी मर रहे है। लाखो जिरायत पेशा लोग रोजगार के फराहमे में अपना गाव छोड़ कर शहरो की तरफ जा रहे है। अजनास की कीमतों मे गैर-मामूली इजाफा हो रहा है। चावल की कीमत 80 रुपये से 125 रुपये हो चुकी है। ज्वार की कीमत 60 रुपये से 90 रुपये किवटल जा चुकी है। बाज लोग इस कसमकुर्मी की हालत खुदकशी कर चुके है। चोरी और लूटमार की वारदातें हर जगह हो रही है। अगर आइन्दा एक हफ्ते मे कुछ बारिश हो जाय तो थोड़ी बहुत फसल बच जायगी। मगर पैदावर बहुत ही कम होगी। आन्ध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपया फिलफौर ड्राउट रिलीफ के कामों के लिए मजूर किया है जिस के तहत पीने के पानी की बावलियों को गहरा करने का काम कर रहे हैं और डिस्ट्रेस तकावी लोन दे रहे हैं। माल-गुजारी और कर्जों की वसूली मुल्तवी कर दी गई है। फेयर प्राइस शाप्स के जरिए से एक हजार टन चावल तकसीम किया जा रहा है। इतने बड़े मसले से निपटने का सवाल हुकूमत आन्ध्र के कुदरत के बाहर है। कल हम ने प्राइम मिनिस्टर को याददाश्त दी हैं और माग

की है कि सरकार फौरी स्टडी टीम को आन्ध्र भेजे और फिलवक्त 10 करोड रुपये मजूर किएं जायें। इस मे देरी न की जाए।

मै एक शेर अर्ज करता हू :—

हम ने माना कि तगाफिल न करोगे लेकिन
खाक हो जाएंगे हम तुम को खबर होने तक ।।

क्रानिक ड्राउट अफेक्टिड एरियाज के लिए एक मास्टर प्लान तैयार की जानी चाहिए और गोदावरी प्रोजेक्ट और इस के नार्थ कैनाल को फौरी तरमील की जाय।

श्री टी० डी० कांबले (लातूर) . सभापति महोदय, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हर साल कही ज्यादा बारिश होती है, कही कम बारिश होती है और कही बिलकुल ही नही होती। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार मे काफी बारिश हो कर बाढ़ आ गई है, दूसरी तरफ अगर पश्चिम मे देखेंगे महाराष्ट्र के सात जिले तो ऐसे है जहा जून के आरम्भ से लेकर अब तक बिलकुल पानी नही बरसा है, जहा पर काश्तकार बीज भी नही बो सके है। मै उसी क्षेत्र का चित्र आप के सामने रखना चाहता हू। आज वहा पर यह स्थिति है कि जानवरो को पीने के लिए पानी नही है, आदमियो को भी पीने के लिए पानी नही है, कई गाव तो उठकर बाहर जा रहे है, इतना बडा सकट उन के सामने आ गया है। मै उन जिलो के बारे मे कह रहा हू जो मराठावाड के जिलों का है, जहा निजाम साहब के जमाने मे न कोई कल कारखाने है, न रेलवे लाइन है, न उन्नति के कोई साधन है। वहा के लोग सिर्फ मजदूरी कर के, काश्तकारी करके, अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब ऐसी हालत मे जब कि वहा पर पानी न बरसा हो, बीज न बोये जा सकते हो, तो वे लोग क्या करेगे। वहा काम करने के लिए स्थायी काम नही है, पाने के लिये पानी नही है, जानवरों के लिए चारा नही है, एक भयकर दुर्भिक्ष की स्थिति हो रही है, तो मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि आप वहा पर फौरन अपनी टीम भेजें, सर्वे करायें, जो मदद उन को दी जा सकती है, उसे जल्द पहुंचाने का प्रयत्न करे।

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि "हम वहा पर लोगो को काम देगे, सस्ते अनाज की दुकाने खोलेंगे, लोगो को भूखा नही मरने दिया जायेगा, लेकिन यह इतना बड़ा काम है जिसको महाराष्ट्र सरकार अकेले बरदाश्त नही कर सकती है। जहा पर आज 10 लाख आदमी काम कर रहे है, लेकिन अब यह तादाद बढ कर 20 लाख तक हो जायेगी, मजदूर तो काम कर रहा है, लेकिन अब किसान भी मजदूर बन कर खडा हो गया है, क्योंकि उसके पास अनाज नही है, जानवरो को चारा नही है, पानी नही है भूखो मरने के सिवा अब उस के लिये क्या रह गया है।

मै इस मौके पर मन्त्री महोदय को खास कर कहना चाहता हू, यह ठीक है कि किसान मजदूरी तो कर सकता है, उसमे मजदूरी करानी चाहिये, लेकिन जो ऐसे लोग है, जो मजदूरी भी नही कर सकते है-जैसे आर्टिजन्ज है, कारीगर है, उन के लिये क्या हो रहा है। उस के भूखे मरने की नौबत आ गई है, क्योंकि वह दूसरा काम नही कर सकता है। आप ने बैंको का राष्ट्रीयकरण किया, हम बहुत बडी बडी बाते करते है कि उन को काफी पैसा मिलेगा, लेकिन हमारे पास तो कुछ नही मिल रहा है। वे लोग पूछते है कि हम इस वक्त क्या करे, मजदूरी की ताकत नही है, वे काम कर नही सकते है, वे क्या करे। हमारे सुनार है, लुहार है, कारपेन्टर है-ये लोग कहा जाये ? इन के लिये सरकार की तरफ से क्या सहूलियत है। मै मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूगा कि वे इस तरफ ध्यान दें। जो लोग इस तरफ बेकार है, उन का इसमे कोई गुनाह नही है, यह तो एक आफत आई हुई है, सकट आया हुआ है, इस लिये जो सरकार वहा पर है उस की यह जिम्मेदारी है कि उन को काम दे, उनके

[श्री टी० डी० कांबले]

जीवन रक्षा का प्रयत्न करे ताकि उनके पारिवारिक जीवन को कोई खतरा पैदा न हो सके।

मराठवाड़ा के हमारे इस क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जायकवाड़ी प्रोजेक्ट है और भी कई प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। आप जानते हैं मराठावाडा का एरिया ऐसा एरिया है, जहां कोई कारखाना नहीं है, एक-दो मिले हैं, वह भी बन्द होने की नौबत मे है। इस लिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि जो छोटे छोटे बांध नदियों पर बनने वाले हैं, उन को शीघ्र शुरू किया जाय ताकि इन लोगों को काम मिल सके। यह बात भी ठीक है कि आप काम शुरू कर देंगे, लेकिन वहां पर साधनों की भी कमी है जिनके बगैर यह काम हो नही सकते। जैसे वहां पर रोलर्स नही है, दूसरी मशीनें नही है, जिनके न होने से काम बन्द हो जाता है। मै चाहता हूं कि काम खोलने के साथ साथ वहां पर साधन भी उपलब्ध किये जायें। सरकार पैसा लगाकर काम शुरू करने को तैयार है, लेकिन मशीनरी नहीं है, काम की गिनती करने के लिए नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं हैं। मै चाहता हूं कि इन्जीनियरिंग कालिजिज मे जिन लोगों का लास्ट-ईयर है, उन को आप इस काम पर लगायें, जिससे काम की गिनती करने वाले भी मिल सकें इन सब चीजों की सहूलियतें वहां पर पैदा की जायें।

आज छोटे काश्तकारों के लिये इतनी परेशानी है कि मजदूरी के लिये भी वे जा नहीं सकते, घर में काम नही कर सकते हाथ में पैसा नहीं है, खाने के लिये अनाज नहीं है—इनके लिये क्या इन्तजाम सरकार करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि ऐसे काश्तकारों को लोन दिया जाय, ताकि वे अपना काम कर सकें, अपनी जिन्दगी का निर्वाह कर सकें, उन को काम देने के लिये वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा उपलब्ध होना चाहिये। आज वहां पर 20 से 25 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, मैं चाहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट से मदद देकर उस काम को पूरा किया जाय।

MR. CHAIRMAN: Before I call upon the next Member, kindly listen. The Chair will call upon the Minister to reply at 6.20. Then, Shri F. A. Ahmed will speak for 10 minutes. So, the debate will continue up to 7 O' clock.

There are a number of names in the list. There is a large number. But everybody will get time provided everybody confines himself to the time allotted to him—three to four minutes. Now, Shri Md. Jamilurrahman. (*Interruption*) Let there be order in the House.

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): May I request that the Ministers can reply after 7 p. m. ?

MR. CHAIRMAN: Your suggestion cannot be accepted.

17.46 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज): चेयरमैन साहब, यह बिलकुल जाहिर बात है कि बाढ़ एक रेग्यूलर फीचर हो चुकी है। जब नदी है तो बाढ़ का आना जरूरी है। सवाल यह पैदा होता है कि इसे रोका कैसे जाय। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मैं पहले पर्टिकुलरली उसी क्षेत्र की बातें आप के सामने रखना चाहता हूं, सारे हिन्दुस्तान के बारे में तो दूसरे मेंम्बरों ने अर्ज किया ही है। मेरे इलाके में बहुत सारी नदियां पड़ती हैं—महानदी, मेछी, कनकई, पनार, परवान, बकरा, वगैरह वगैरह, जिनको "सौरे आफ ड़ी डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया" कहा जाता है। दूसरी तरफ मेरे सूबे मे जो नदिया हैं, उनके नाम हैं—कोसी, गंगा, बाघमती, भूथी बालान, वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से भी मिला था, कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग में भी मैंने इस सवाल को उठाया था कि इनके लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है। पिछले 22 वर्षों में हमने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिये मैं

सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हू कि जिन नदियो के मैने नाम गिनाये है, उनकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान जाना चाहिये और फ्लड-कन्ट्रोल के मेजर्स कदम वार-फूटिंग पर लिये जाने चाहिये ।

दूसरी बात—कोसी प्राजेक्ट लाखो करोड रुपया खर्च कर के बनाया गया है । प्राजेक्ट तो बन गया, लेकिन उसका रिपरक्शन क्या हुआ, उसके लिये जो पानी छोडा जाता है और जो वाटरलागिग वहा पर होता है, उसके लिये कोई इन्तजाम नही है । हजारहा-हजार एकड जमीन पानी के अन्दर है और पिछले 6-7-8 वर्षों से उसके लिये कोई इतजाम नही हो सका है ताकि वहा से पानी की निकासी हो सके, खेत खाली हो तो है नही कि फसल बोई जाय और उगाई जाय ।

तीसरी बात—इस बाढ मे मेरे इलाके मे (डिस्ट्रिक्ट आफ पूर्णिया) मे 15-16 लाख आदमी इफैक्टेड है । बिहार सरकार की जून की रिपोर्ट मेरे पास है, जून से वहा पर बाढ आई हुई है, लेकिन उस वक्त से आज तक सरकार की तरफ मे कोई कान्क्रीट स्टेप्स नही उठाये गये है, जिससे वहा के लोगो को कुछ राहत मिल सके । वहा पर जो फ्लड आया था उसकी सूचना मैने प्रधान मत्री को भी दी थी, उनको मेमोरेण्डम भी दिया था नेशनल हाइ-वे न० 31 टूट गई है, बरौनी खतरे मे है, फर्टिलाइजर और आयल रिफाइनरी फैक्टरी खतरे मे है--इनके लिये फौरन इतजाम किया जाना चाहिये । मैंने अपने मेमोरेण्डम मे इन सब बातो का जिक्र किया है और 10-15 दिन पहले यह मेमोरेण्डम दिया था । वहा पर एक सडक N. H 31 है जो अमीनगाव जाती है, दरभगा से लेकर फार-बिसगज तक जो Lateral road का प्लान था वह बन्द हो गया है, रेलवे लाइन टूट गई है, जिससे नार्थ-बिहार बिलकुल कट-आफ हो गया है । अगर इस सड़क (N. H. 31) को ऊचा बनाया जाता तो शायद ऐसी नौबत नही आती । डगमरा बैरेज बना दिया गया होता और अगर उसके जरिये पानी को कट्रोल किया जाता, तो काफी फ्लड कन्ट्रोल हो सकता था । हमारे अनरेबिल मिनिस्टर साहब वहा गये थे ..

सभापति महोदय · हम अब किसी को स्पीच के लिये एलाउ नही करेंगे, आप सिर्फ सवाल पूछिये ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान . हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री हनुमन्तैया साहब 7 अगस्त को जब वहा पर गए तो उन्होने कहा कि मैंने बिल्कुल समुन्दर देखा । इसी तरह से ललित बाबू भी जब बिहार मे गये तो उन्होने कहा कि हमको गाव ही नही मिले, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था ।

सभापति महोदय अब आप बन्द कीजिये ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैं प्वाइट आफ आर्डर रेज करता हू ।

सभापति महोदय कोई प्वाइट आफ आर्डर नही है, आप बन्द कीजिये ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान · दूसरे लोग बीस बीस मिनट बोले है ।

सभापति महोदय बाले होंगे । मैने आप को पाच मिनट दे दिया है । अब आप बन्द कीजिये ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मेरा तो लिस्ट म नाम था और जिनका नाम नही था उनको भी आपने बोलने का मौका दिया है ।

सभापति महोदय : अब आप बैठिये । मैं एलाउ नही करता हू ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : यह तो इन-जस्टिस है । मुझे बोलने का मौका नही मिला इसका मुझे बहुत दुख है । हम यहा पर इस सदन की खूबसूरती देखने के लिये नही आये है । हम यहा पर जनता के वोट से जनता की

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

बात कहने के लिये आये हैं और आप के द्वारा सरकार तक बात पहुंचाना मेरा फर्ज है ।

सभापति महोदय : मैं आपको एलाऊ नही करूंगा । ला मिनिस्टर ।

17.52 hrs

STATEMENT RE : REPORTED APPEARANCE OF ATTORNEY-GENERAL IN SUPREME COURT ON BEHALF OF MYSORE IN CAUVERY WATERS DISPUTE

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) : I was informed that a question was raised in the morning whether the Attorney General of India appeared for the State of Myrore in the suit which has been filed by the Government of Tamil Nadu in respect of the Cauvery waters dispute in the Supereme Court. It was also asked how the Attorney General could be authorised to appear for the State of Mysore. I want to make it clear that as a matter of fact the Attorney General did not appear for the State of Mysore. The Attorney General appeared for the Union of India. It is no doubt true that the Governor of Mysore requested me to allow the Attorney General to appear for Mysore, and two officers, the Advocate General and the Law Secretary of the Mysore Government, had come here to meet me for requesting me to allow the Attorney General to appear for the State of Mysore, but I had made it clear that in a dispute like this the Union Government could not align itself with anyone of the two parties and that I was not in a position to comply with their request. In fact the Attorney General did not appear for Mysore.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : What made Mr. Viswanathan raise the question was a press report that the Governor of Mysore had stated that he had asked the Attorney General of India to appear for Mysore. Now that has been contradicted.

SHRI H. R. GOKHALE : The Governor of Mysore did request me to permit the Attorney General, and the two officers met me but I said I could not comply.

SHRI SEZHIYAN : This shows that Mr. Dharma Vira is not aware of the provisions of the Constitution and the procedure of the Government, and he is occupying the gubernatorial post in a State.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : This morning I requested the Government to bring a Resolution demanding the release of Sheikh Mujibur Rehman. I know that it is not possible to do this at the fag end, but I would like to get some assurance from the hon. Minister Shri Raj Bahadur that the Government will do its best. I only request you to ask him to say something.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJBAHDUR) : The Prime Minister may come at about 6.30. At that time she might say something if you put this question.

SHRI DHARAMRAO AFZALPURKAR (Gulbarga) : The Governor of Mysore has got the right to request the Government of India to permit the Attorney General to appear for Mysore.

17.57 hours

DISSCUSSION RE : FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN THE COUNTRY—*Contd.*

सभापति महोदय : जमीलुर्रहमान जी, आप सिर्फ सजेस्चन्स दे दीजिये ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैं यह अर्ज कर रहा था क्या सरकार कोई ठोस योजना 7—8 साल के लिये बनायेगी जिससे पूरे इंडिया में और खास तौर पर पूर्णिया में फ्लड कन्ट्रोल हो सके ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार पूर्णियां, दरभंगा और सहर्सा जिलों के ब्लाक्स